

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में,

Shri Rahul Verma Advocate (LL.M)
Supreme Court of India,
Additional Advocate General for State of Uttarakhand

पत्रांक 3510 / तीस-खनन / 2022-23,

दिनांक:- मार्च 21, 2023,

Sub : For URGENT compliance of directions issued by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Vide its order dated 24-02-2023

In Re: O.A No.429 of 2022
Ridhima Pandey-Vs- State of Uttarakhand

कृपया, उपयुक्त विषयक अपने पत्र दिनांक:-02.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अल्प अवधि का पट्टा एवं उससे संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका (पीआईएल) संख्या:-47 OF 2022 में पारित आदेश दिनांक:-14.02.2023 की प्रति, इस कार्यालय के आदेश संख्या:-280/ST-रिवर ड्रेजिंग/2020-21, दिनांक 26 फरवरी, 2021 से 4 माह या अनुज्ञामात्रा को हटाये से पूर्व की अवधि हेतु अनुमति/अनुज्ञापत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका (पीआईएल) संख्या:-47 OF 2022 में पारित आदेश दिनांक:-14.02.2023 के अनुपालन के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या:-280/ST-रिवर ड्रेजिंग/2020-21, दिनांक 26 फरवरी, 2021 से 4 माह या अनुज्ञामात्रा को हटाये से पूर्व की अवधि हेतु अनुमति दी गयी, जिसकी अवधि दिनांक:-26 जून, 2021 को समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में मा. हरित प्राधिकरण द्वारा रिधिमा पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में समिति द्वारा दिनांक:-23, 24 अगस्त, 2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण आख्या में भी.....No mining Activity has been undertaken so far का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त वर्णित संयुक्त निरीक्षण आख्या की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,



(नरेन्द्र सिंह भण्डारी)
जिलाधिकारी,
चम्पावत।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून के शासनादेश संख्या:-137/VII-1/2020/90ख/16 दिनांक:-31 जनवरी, 2020 के क्रम में ग्राम झालाकुड़ी, नौलापानी तथा उचौलीगोठ तहसील पूर्णांगिरी जनपद चम्पावत अन्तर्गत लधिया नदी में जमा आर0बी0एम/मलवे के निस्तारित हेतु दिनांक:-15.12.2020 को उप जिलाधिकारी कार्यालय पूर्णांगिरी में खुली नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। सम्पन्न कराई गई नीलामी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	खुली नीलामी हेतु चिन्हित ग्राम/स्थल का नाम	उच्चतम बोली की धनराशि	बोली की दिनांक को जमा धनराशि	उच्चतम बोली की अवशेष जमा धनराशि	उच्चतम बोली का 17 प्रतिशत धनराशि	उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत डी0एम0एफ0 जमा धनराशि का विवरण	कुल जमा की गयी धनराशि का विवरण	उच्चतम बोलीदाता का नाम व पता
1	लधिया नदी, ग्राम झालाकुड़ी खसरा नं० 22, 23 मध्ये 0.75 है। (25500 घनमीटर)	1762500	625688	1136812	299625	440625	2502750	श्री योगेन्द्र ज्याल पुत्र कर्णध्वज सिंह ज्याल, निवासी टनकपुर।
2	लधिया, ग्राम नौलापानी, खसरा नं० 42/5591 मध्ये 1.00 है। (30000 घनमीटर)	2350000	834250	1515750	399500	587500	3337000	श्री उमेश खर्कवाल पुत्र रामदत्त खर्कवाल, निवासी चम्पावत।
3	शारदा नदी, ग्राम उचौलीगोठ खसरा सं-335/2, क्षेत्र 2.00 है। (60000 घनमीटर)	14670000	5207850	9462150	2493900	3667500	35501400	श्री तरुण पंत (मै० शिव शक्ति ट्रेडर्स) पुत्र श्री दिनेश पंत, निवासी टनकपुर।

उपरोक्त उच्चतम बोलीदाताओं द्वारा बोली की धनराशि तथा डी0एम0एफ0 एवं अन्य कर रॉयल्टी की 42 प्रतिशत धनराशि में से 17 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853 अलौह धातु एवं धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रियायती शुल्क, 01 स्वत्व शुल्क एवं 25 प्रतिशत की धनराशि जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास चम्पावत के यूकों बैंक खता संख्या:-32040110011362 में जमा कर दी गयी है। सम्पन्न कराई गई नीलामी में उच्चतम बोलीदाताओं की नीलामी को जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत पत्र संख्या:-1617/XXX-10/रिवर ट्रेनिंग/2019-20, दिनांक:-01 जनवरी, 2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः उपरोक्त उच्चतम बोलीदाताओं को शासनादेश संख्या:-137/VII-1/2020/90ख/16 दिनांक:-31 जनवरी, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम झालाकुड़ी एवं नौलापानी तहसील पूर्णांगिरी जनपद-चम्पावत अन्तर्गत लधिया नदी, शारदा नदी में संयुक्त सीमांकन स्थल से जमा आर0बी0एम0/मलवे के निस्तारण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

शर्तें

- (1) सीमांकित क्षेत्र में नदी तल के अनुमन्य गहराई तक ही चैनेलाईजेशन का कार्य करना होगा।
- (2) आवेदक द्वारा उपखनिज के तौल हेतु नजदीकी धर्मकांटे से अनुबन्ध किया जाना होगा एवं अनुबन्ध की प्रति इस कार्यालय एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) आवेदक द्वारा आदेश प्राप्त उपरान्त ई-रवन्ना प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) ई-रवन्ना जारी होने से अनुज्ञा की अवधि मानी जायेगी। निर्धारित अनुज्ञा की अवधि से आर0बी0एम0/मलवे का निस्तारण 04 माह या अनुज्ञामात्रा को हटाने से पूर्व की अवधि जो हो, के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा।
- (5) सीमांकित स्थल पर स्थित मलवे का निस्तारण हेतु अन्य देयकों व टैक्स आदि का भुगतान नियमानुसार आवेदक द्वारा किया जायेगा।
- (6) आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के नियमों/प्राविधानों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) प्रस्तावित क्षेत्र से मलवा/आर0बी0एम0 चुगान एवं परिवहन के दौरान किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उसका उत्तदायित्व आवेदक का होगा।

(Handwritten Signature)

311
किसी भी वाहन में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज की मात्रा हेतु अभिवहन पास जारी किया जाता है, तो वाहन स्वामी के साथ-साथ सम्बन्धित आवेदक के विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा एवं अनुमति निरस्त की कार्यवाही की जायेगी।

(09) सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद किसी भी दशा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। उक्त अवधि में किये जाने वाला खनन कार्य अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा। तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(10) यदि मुख्य मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग) पर कोई वाहन बिना रवन्ना एवं भार प्रमाण पत्र के पाया जायेगा, तो अवैध खनन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) अनुमति क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में अवैध खनन होने की स्थिति में आवेदक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा, उससे पूर्व मौके के फोटोग्राफस लोने होंगे, जिससे अवैध खनन की कार्यवाही तदनुसार की जा सके।

(12) आवेदक द्वारा अनुमति क्षेत्र में अनुमति/अनुज्ञा का पूर्ण विवरण सहित बोर्ड लगाया जायेगा।

(13) सिंचाई विभाग द्वारा अनुज्ञा स्थल का नियमित रूप से मानिट्रिंग की जायेगी।

(14) आवेदक के विरुद्ध उत्तराखण्ड रीवर ट्रेनिंग नीति-2020 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में अनुज्ञा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

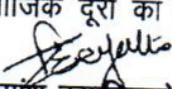
(15) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संकमण से बचाव हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) आवेदक द्वारा मलवा/आर0बी0एम0 की निकासी निर्धारित समय अन्तर्गत अनिवार्य रूपसे की जानी होगी। निकासी की अवधि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जायेगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि मलवा/आर0बी0एम0 की निकासी किन्हीं कारणों से आवेदक द्वारा नहीं की जाती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(17) आवेदक द्वारा खनन स्थल पर एक पोकलैण्ड अथवा 01 जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग खनन कार्य में किया जायेगा।

(18) आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार दी गई शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा रीवर ट्रेनिंग नीति-2020 के अन्तर्गत दी गयी अनुज्ञा/अनुमति किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(19) कोविड-19 की गाईडलाइन्स के अनुसार खनन क्षेत्र में मास्क, सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा।


(हिमांशु कफटिया)
उप जिलाधिकारी,
पूर्णागिरी (टनकपुर)।

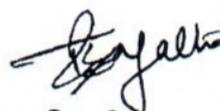
कार्यालय उप जिलाधिकारी, पूर्णागिरी (टनकपुर) जनपद-चम्पावत ।

संख्या:-280/st-रिवर ट्रेनिंग/2020-21,

दिनांक:- 26 फरवरी, 2021।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
2. पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
4. प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग/तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
5. पुलिस उपाधीक्षक, टनकपुर।
6. तहसीलदार, पूर्णागिरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सीमांकन क्षेत्र से नियमानुसार खनन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
7. उप निबन्धक, चम्पावत।
8. सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, टनकपुर।
9. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, टनकपुर/थानाध्यक्ष बनबसा।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट।
11. उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, चम्पावत।
12. उपरोक्त बोलीदाता।


उप जिलाधिकारी,
पूर्णागिरी (टनकपुर)।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

536

संख्या:-1617 /XXX-10/रिवर ट्रेनिंग /2019-20, दिनांक:- 01 जनवरी, 2021,

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
पूर्णागिरि (टनकपुर)।

विषय:-

रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के अन्तर्गत ग्राम उचौलीगोट, झालाकूड़ी एवं नौलापानी, तहसील पूर्णागिरि, जनपद चम्पावत अन्तर्गत लधिया नदी, शारदा नदी में जमा आर0बी0एम0/मलवे के निस्तारण हेतु दिनांक:-15.12.2020 को आयोजित खुली नीलामी को स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या:-147/एस0टी-री0ट्रे0/2020-21, दिनांक:- 21 दिसम्बर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत आर0बी0एम0/मलवा निस्तारण किये जाने हेतु निम्नवत् ग्रामों के खसरा नम्बरान में नीलामी की कार्यवाही की गयी है:-

क्र० सं०	नदी का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	उप खनिज की मात्रा (घनमीटर में)	ऑगणित रॉयल्टी	उच्चतम बोली की धनराशि	डी0एम0एफ0 एवं अन्य कर रॉयल्टी का 42 प्रतिशत	उच्चतम बोलीदाता का नाम व पता
01	लधिया	झालाकूड़ी	22, 23	0.75 हे०	22500 घनमीटर	17,32,500.00	17,62,500.00	7,40,250.00	श्री योगेन्द्र ज्याल पुत्र कर्णध्वज सिंह ज्याल निवासी टनकपुर।
02	लधिया	नौलापानी	42/5591	1.00 हे०	30000 घनमीटर	23,10,000.00	23,50,000.00	9,87,000.00	श्री उमेश खर्कवाल पुत्र श्री रामदत्त खर्कवाल निवासी चम्पावत।
03	शारदा	उचौलीगोट	335/2	2.00 हे०	60000 घनमीटर	92,40,000.00	1,46,70,000.00	61,61,400.00	श्री तरुण पन्त पुत्र श्री दिनेश चन्द्र पन्त निवासी टनकपुर।

आपके द्वारा उपरोक्त ग्रामों में कराई गयी खुली नीलामी में उच्चतम बोलीदाताओं के द्वारा बोली गयी नीलामी को अनुमोदित/स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश दिनांक:-30.12.2020 से आपके द्वारा कराई गयी उक्तानुसार खुली नीलामी का अनुमोदन किया गया है तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जिन लॉट्स की नीलामी नहीं हो पाई है, उनकी पुनः नीलामी कराई जाय।

अतः आप उक्त नीलामी से प्राप्त उच्चतम बोली के सापेक्ष रायल्टी की 25 प्रतिशत धनराशि डी0एम0एफ0 में तथा 17 प्रतिशत धनराशि अन्य कर इस प्रकार कुल रायल्टी का 42 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के निर्देशानुसार जिन लॉट्स की नीलामी नहीं हो पाई है, उनकी पुनः नीलामी कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(त्रिलोक सिंह मत्तोलिया)
अपर जिलाधिकारी,
चम्पावत।

प्रतिलिपि:-'उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
चम्पावत

(535)

शेषक,

उप जिलाधिकारी,
पूर्णागिरी (टनकपुर) ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत ।DM
23/12/2020

संख्या- 147/एस0टी0-री0ट्रे0/2020-21

दिनांक:- 21 दिसम्बर, 2020 ।

विषय- रीवर ट्रेनिंग नीति-2020 के अन्तर्गत ग्राम उचौलीगोट, झालाकुड़ी एवं नौलापानी तहसील पूर्णागिरी जनपद चम्पावत अन्तर्गत लधिया नदी, शारदा नदी में जमा आर0बी0एम0/मलबे के निस्तारण हेतु दिनांक 15.12.2020 को आयोजित खुली नीलामी को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महोदय के कार्यालय पत्र संख्या:-1033/XXX-10 (रिवर ट्रेनिंग)/2017-21, दिनांक:-02 दिसम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-137/VII-A-1/2020/90-ख/16 दिनांक:-31 जनवरी, 2020 द्वारा ग्राम उचौलीगोट, झालाकुड़ी, नौलापानी, नायकखेड़ा तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) जनपद-चम्पावत अन्तर्गत लधिया नदी, किरौड़ा नाले एवं शारदा नदी में जमा आर0बी0एम0/मलबे के निस्तारण हेतु निहित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया ।

उक्त निर्देशों के क्रम में ग्राम उचौलीगोट, झालाकुड़ी, नौलापानी एवं नायकखेड़ा तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) जनपद-चम्पावत अन्तर्गत लधिया नदी, किरौड़ा नाले एवं शारदा नदी में जमा आर0बी0एम0/मलबे के निस्तारण हेतु खुली नीलामी हेतु प्रेस नोट जारी कर जनपद के स्थानीय व्यक्तियों व संस्थाओं से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये। निर्धारित तिथि 15.12.2020 को 51 आवेदनकर्ताओं के द्वारा तहसील सभागार में आर0बी0एम0/मलबे के निस्तारण हेतु खुली नीलामी में प्रतिभाग किया गया। नीलामी का विवरण निम्न प्रकार है-

क0 सं0	नदी का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	उप खनिज की मात्रा (घनमीटर में)	आंगणित रायल्टी	उच्चतम बोली की धनराशि	डी.एम. एफ. एवं अन्य कर रॉयल्टी का 42 प्रतिशत	उच्चतम बोलीदाता का नाम व पता
1	लधिया	झालाकुड़ी	22, 23	0.75 है.	22500 घ.मी.	17,32,500	1762500	7,40,250	श्री योगेन्द्र ज्याल पुत्र कर्णध्वज सिंह ज्याल, निवासी टनकपुर।
2	लधिया	नौलापानी	42/5591	1.00 है.	30000 घ.मी.	23,10,000	2350000	9,87,000	श्री उमेश खर्कवाल पुत्र रामदत्त खर्कवाल, निवासी चम्पावत।
3	शारदा	उचौलीगोट	335/2	2.00 है.	60000 घ.मी.	92,40,000	14670000	61,61,400	श्री तरुण पंत पुत्र दिनेश पंत, टनकपुर।

उच्चतम बोलीदाताओं से बोली की तथा डी0एम0एफ0 एवं अन्य कर की सम्पूर्ण धनराशि की 25 प्रतिशत की धनराशि सम्बन्धित लेखाशीर्षक एवं बैंक ड्राफ्ट एवं डी0डी0 जमा करा दी गयी है। नीलामी हेतु निर्धारित 08 लॉट में से किरौड़ा नाले में अवस्थित 5 लॉटों में से लॉट 04, 05 एवं 08 में 01 आवेदन तथा लॉट 06 एवं 07 में कोई आवेदन न आने के कारण निरस्त की गयी।

अतः अनुरोध है कि सर्वाधिक बोलीदाताओं से अवशेष धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाने हेतु उच्चतम बोलीदाताओं की नीलामी को अनुमोदित/स्वीकृत करने की कृपा करें।

भवदीय,

(हिमांशु कफलिया)

उप जिलाधिकारी,
पूर्णागिरी (टनकपुर) ।

:: कोविड-19 से बचाव ::

- मास्क पहने। ● 2 गज की दूरी बनाये रखें। ● साबुन/हैंडबॉस से हाथ धोये। ● सेनेटाईजर से हाथ साफ करें। ● सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर जांच कराये।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या:-1033 /XXX-10 (रिवर ट्रेनिंग)/2017-18/(2020-21) दिनांक:- 02 नवम्बर 2010।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
पूर्णागिरि (टनकपुर)।

विषय:-

रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के माध्यम से मानसून अवधि में नदियों, नालों में बाढ़/जल स्तर बढ़ने से होने वाले व्यापक जन-धन हानि की रोकथाम हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-101/एस0टी0-रिवर ट्रेनिंग/2020-21, दिनांक:-20 नवम्बर, 2020 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत आर0बी0एम0/मलवा का निस्तारण किये जाने हेतु निम्नवत् क्षेत्रों का प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है :-

क्र0 सं0	नदी का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हे0 में	खसरा संख्या	प्रस्तावित रिवर ट्रेनिंग हेतु क्षेत्र वर्ग मीटर में	उप खनिज आर0बी0एम0/मलवा की मात्रा (घनमीटर में)	ऑगणित रायल्टी (रू0 में)	डी0एम0एफ0 एवं अन्य कर रायल्टी का 42 प्रतिशत
01	लधिया नदी	झालाकूड़ी	0.75	22, 23 म0	150X50=7500	22500	17,32,500.00	7,27,650.00
02	लधिया नदी	नौलापानी	1.00	42/5591 म0	200X50=10000	30000	23,10,000.00	9,70,200.00
03	शारदा	उचौलीगोट	2.00 हे0	335व	100X200=20000	60000	92,40,000.00	38,80,800.00
04	किरौड़ा नाला	नायकखेड़ा	12.901	296	400X50=20000	60000	92,40,000.00	38,80,800.00
05	किरौड़ा नाला	नायकखेड़ा	12.901	296	400X50=20000	60000	92,40,000.00	38,80,800.00
06	किरौड़ा नाला	नायकखेड़ा	12.901	296	400X50=20000	60000	92,40,000.00	38,80,800.00
07	किरौड़ा नाला	नायकखेड़ा	12.901	296	400X50=20000	60000	92,40,000.00	38,80,800.00
08	किरौड़ा नाला	नायकखेड़ा	12.901	296	400X50=20000	60000	92,40,000.00	38,80,800.00

आपके द्वारा उपरोक्त चिन्हित क्षेत्र से रिवर ट्रेनिंग नीति-2020 के माध्यम से उप खनिज/आर0बी0एम0 के निस्तारण हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आपके द्वारा प्रस्तावित उक्त क्षेत्रों से आर0बी0एम0/मलवा निस्तारण के संबंध में शासनादेश संख्या:-137/VII-A-I/2020/90-ख/16, दिनांक:-31 जनवरी, 2020 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(त्रिलोक सिंह मर्तोल्या)
अपर जिलाधिकारी
चम्पावत

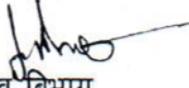
प्रतिलिपि:-उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी
चम्पावत

जिलाधिकारी महोदय चम्पावत द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के अर्न्तगत तहसील पुठानगिरा के ग्राम पुचौलीगिठ में शारदा नदी में रिवर ट्रेनिंग हेतु स्थल चयनित करने हेतु दिनांक 03-11-2020 को संबंधित विभागों राजस्व विभाग, खनन विभाग, सिचाई विभाग, वन विभाग के द्वारा किया गया संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित स्थल की स्थिति निम्नवत है:-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	नदी का नाम	खाता खतौनी एवं खसरा संख्या	रक्बा	प्रस्तावित रिवर ट्रेनिंग का क्षेत्रफल(वर्ग मी में)	उपखनिज(आर०बी० एम०/मलवा) की मात्रा(घन मी०)	आंगणित रायल्टी की घनराशि (रु० में)	जिला खनिज फाउन्डेशन एवं अन्य कर की घनराशि(रायल्टी का 42 प्रतिशत)(रु० में)
1.	<u>पुचौलीगिठ</u>	<u>शारदा</u>	<u>2422/2</u> <u>समूचा</u> <u>335/2</u> <u>मरुचे</u>	<u>2.50 हे०</u>	<u>150 X 200 मी०</u> <u>= 20000 वर्ग मी०</u>	<u>60000</u> <u>घ० मी०</u>	<u>19,40,000/-</u> <u>92,40,000/-</u>	<u>19,40,000/-</u> <u>38,80,800/-</u>

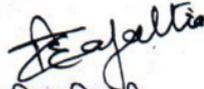
उपरोक्त रिवर ट्रेनिंग स्थल से उपखनिज(आर०बी० एम०/मलवा) का निस्तारण हेतु 04 माह का समय अवधि तथा 01 (एक) पोकलैण्ड एवं 01 (एक) जे० सी० बी० से उठान किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के अर्न्तगत की जाती है।


राजस्व विभाग


सिचाई विभाग


वन विभाग


उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी
चम्पावत/पिथौरागढ़


उपजिलाधिकारी

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND
AT NAINITAL

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE SRI VIPIN SANGHI
AND
HON'BLE SRI JUSTICE RAVINDRA MAITHANI

14TH FEBRUARY, 2023

WRIT PETITION (PIL) No. 47 OF 2022

Between:

Dinesh Kumar Chandola.

...Petitioner

and

Union of India and others.

...Respondents

Counsel for the petitioner. : Mr. Dushyant Mainali, the learned
counsel.

Counsel for respondent no. 1. : Mr. Lalit Sharma, the learned Standing
Counsel for the Union of India.

Counsel for respondent nos. 2 to 7. : Mr. S.N. Babulkar, the learned
Advocate General assisted by Mr. C.S.
Rawat, the learned Chief Standing
Counsel for the State of Uttarakhand.

Counsel for respondent no. 8. : Mr. Rajeev Bhatt, the learned counsel.

Counsel for respondent no. 9. : Mr. Aditya Pratap Singh, the learned
counsel.

JUDGMENT : (per Sri Vipin Sanghi, C.J.)

We have heard Mr. Dushyant Mainali, the learned counsel for the petitioner, and Mr. S.N. Babulkar, the learned Advocate General assisted by Mr. C.S. Rawat, the learned Chief Standing Counsel for the State of Uttarakhand, and proceed to dispose of this Public Interest Litigation.

2. The challenge raised in this Writ Petition (PIL) is to the Government Order dated 07.01.2022, and the subsequent permission granted for mining/ dredging of Nandhaur River in the Eco-Sensitive Zone of Nandhaur Wildlife Sanctuary. The petitioner also seeks a direction to the respondents to notify and categorize the zones, where mining is prohibited in the State of Uttarakhand, in consonance with the guidelines issued by respondent no. 1, i.e. the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of the Union Government.

3. By the order dated 07.01.2022, the State Government had permitted M/s A.P.S. Infra Engineers Private Limited to carry out the activity of dredging in the Upper Nandhaur Chorgalia Area for a period of six months, and also to remove the silt and RBM, which is dredged.

4. According to the petitioner, the activity of removing of the mineral, which is dredged, tantamounts to mining, which is completely prohibited in the Eco-Sensitive Zone, which Nandhaur Wildlife Sanctuary is. In this regard, Mr. Mainali has referred to the definition of "*mining operations*" contained in Section 3(d) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, which

means "any operations undertaken for the purpose of winning any mineral".

5. Mr. Mainali has placed reliance on the judgment passed by the Supreme Court in **T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India & Ors., 2010 (13) SCC 740** dated 04.08.2006, on the basis of which the Office Memorandum dated 08.08.2019 was issued by respondent no. 1, i.e. the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of the Union Government. In the light of the aforesaid order passed by the Supreme Court, the Central Government has directed that "*Proposals involving mining of minerals within the ESZ (or) one kilometer from the boundaries of National Parks and Sanctuaries whichever is higher is prohibited in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.4.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.*"

6. The submission of Mr. S.N. Babulkar, the learned Advocate General, is that the activity of dredging is essential to conserve the river and the adjoining areas, as failure to carry out dredging would lead to rise in the riverbed levels, leading to flooding in the adjoining areas

in the rainy season, where agriculture is carried out and habitations are in place. He further submits that the Central Government has also exempted the requirement of obtaining environmental clearance for the purpose of carrying out the activity of dredging and de-silting of, *inter alia*, rivers and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management. In this regard, he has placed reliance on the notification dated 28.03.2020 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Appendix-IX to this notification enlists at Serial Nos. 7 and 12, the activities, in respect whereof exemption has been granted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which reads as follows :-

"APPENDIX-IX

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. *Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.*
8.
9.
10.
11.
12. *Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon*

orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority."

7. The further submission of Mr. Babulkar is that leaving the dredged minerals on the banks of the river, and their non-disposal would also create practical difficulties, inasmuch, as, the silt would flow back into the river in rainy season, and render the activity of dredging nugatory.

8. Mr. Mainali has, with his rejoinder affidavit, placed on record a Joint Inspection Report prepared by a team of Officers, which include the Conservator of Forests, Western Circle, Haldwani, the Deputy Director, MoEF&CC, Dehraun, the Scientist D, CPCB, Lucknow, the Regional Officer, UKPCB, Haldwani, the Sub-Divisional Magistrate, Haldwani, the Geo Chemist, Geology and Mining, Unit-Haldwani, and the Mining Officer, Geology and Mining, Unit- Champawat (Representative of the District Magistrate, Champawat), on the aspect of mining activity in upstream part of Nandhour River, and Upper-stream part of Sharda Barrage, Tanakpur. This report was prepared in the matter of *Ridhima Pandey v. State of Uttarakhand*, (OA No. 429/2022). This report takes note of the impugned order issued by the State Government dated 07.01.2022 above referred to, which permits M/s

A.P.S. Infra Engineers Private Limited to undertake dredging work, and also to remove the silt and RBM for a period of six months from the aforesaid river. The conclusion and recommendation made in this report by the aforesaid Team/ Committee of Officers is that the area in question is rich in bio-diversity and comes within Eco-Sensitive Zone of Nandhaur Wildlife Sanctuary. Hence, mining activity may not be permitted.

9. Mr. Mainali has also referred to the letter dated 28.03.2022 issued by the Divisional Forest Officer, Haldwani Division, wherein he states that the requisite permission is required to be obtained from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as well as from the National Board of Wildlife, before permitting the activity to be carried out in terms of the impugned order dated 07.01.2022.

10. We have heard and considered the rival submissions.

11. There is no doubt that the activity of dredging is essential, and should be carried out in rivers and streams from time to time, so that the riverbed levels are maintained. This is essential to prevent flooding in rainy season, which also causes environmental degradation and

loss of life and property along the path of the river, or the stream concerned. At the same time, it cannot be that under the garb of dredging, what is permitted, and what is actually carried out, is the activity of mining for commercial purposes. The impugned communication permits a private agency, namely M/s A.P.S. Infra Engineers Private Limited, to carry out not only the dredging activity in the Nandhaur Wildlife Sanctuary, but also to win the mineral, which is dredged. For this, undisputedly, it would be essential for the said agency to send its tools and tackles, men and heavy machinery, as well as trucks into the Wildlife Sanctuary to carry out the activity. Thus, what the impugned order dated 07.01.2022 permits M/s A.P.S. Infra Engineers Private Limited to carry out is not merely the activity of dredging, but also the activity of mining. There is no denying the fact that the activity of mining cannot be carried out in an Eco-Sensitive Zone, as we have already noticed above.

12. Another aspect that we cannot lose sight of, is that the grant of a contract to a private agency for the purpose of dredging, and also winning the dredged mineral, would lead to carrying out of the said activity purely for commercial purposes. The private agency would have its commercial interest in mind, and not the

environmental interest, which is the rationale for carrying out the dredging activity in the first place. The dredging activity – which is carried out for environmental reasons, would be limited to the extent it is necessary for achieving that limited objective. However, once the activity is entrusted to a private agency, and that too with a right to carry out mining activity i.e. to win the mineral which is dredged, the extent of dredging that may be carried out on the site is very difficult to monitor or control. The moment the dredged mineral is removed for commercial purposes, the nature of the activity would change from merely dredging to mining, which is clearly prohibited in an Eco-Sensitive Zone.

13. Aforesaid being the position, we cannot permit the respondents to act in terms of their order dated 07.01.2022. The State departments, namely the Forest Conservation Department, and the Agriculture Department, of which the Soil Conservation Division is now a part, should have an active role to play in the carrying out of the activity of dredging in the river in question on its own, without the involvement of a private agency. The activity of mining, i.e. the winning of the dredged mineral, in any case, cannot be permitted. We, therefore, permit the State to undertake the activity of dredging entirely on

its own, without the involvement of private agencies, and with the involvement of the State departments aforementioned.

14. The Writ Petition stands disposed of in the aforesaid terms.

15. Consequently, pending applications, if any, also stand disposed of.

VIPIN SANGHI, C.J.

RAVINDRA MAITHANI, J.

Dt: 14th February, 2023
Rahul

**Joint Inspection Report of Mining activity in upstream part of
Nandhaur River & Upper-stream part of Sharda Barrage, Tanakpur
in the matter of**

Ridhima Pandey vs State of Uttarakhand

in

OA no. 429/2022

Background

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 18 July 2022 in the matter of Ridhima Pandey vs State of Uttarakhand in O.A. no. 429/2022 passed order for verification of factual position related to mining activity mentioned in referenced NGT order and remedial action. Relevant para of Hon'ble NGT order is as below-

"In view of the grievances made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof in case of violation of environmental norms. We accordingly constitute Joint Committee of Regional Office of MoEF& CC at Dehradun, Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand, CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and District Magistrates, Champawat and Nainital and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance."

Copy of the reference NGT order is annexed as **annexure no. 1**.

In compliance of NGT order, joint inspection of areas in question (upstream part of Nandhaur River and Upper-stream part of Sharda Barrage, Tanakpur) was carried out during August 23-24, 2022 by following team members-

1. Shri Deep Chandra Arya, Conservator of Forests, Western Circle, Haldwani.
2. Shri Runa Oraon, Scientist D, CPCB, Lucknow.
3. Dr. Krishnendu Mondal, Dy. Director MoEF&CC, Dehradun.

4. Dr. D.K. Joshi, Regional Officer, UKPCB, Haldwani.
5. Shri Madan Kishore, Geo Chemist, Geology and Mining, Unit-Haldwani.
6. Shri Manish Singh, Sub Divisional Magistrate, Haldwani.
7. Sh. Ravi Negi, District Mining Officer, Champawat

Representative of State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) was not present during joint inspection as SEIAA stands dissolved on the date. Joint inspection by the above said committee was carried out. Salient observation and recommendation based on site inspection and available records of each mining sites is as below-

A. Upstream part of Nandhour River:

Salient Observations:

- a) Nandhour river is originated from Pangoot, Nainital and finally meets with river Kailash. Nandhour river passes through Nandhour Wildlife Sanctuary under Haldwani Forest Division.
- b) Nandhour Wildlife Sanctuary in Haldwani Forest Division is notified as Eco-Sensitive Zone vide MoEF&CC notification dated 22 May 2020. Copy of the said notification is annexed as **annexure no. 2**.
- c) The Secretary ,Industrial Development (Mining) Section -1 Uttarakhand Government has issued a letter dated 07.01.2022 to District Magistrate, Nainital giving permission for River Dredging work to M/s APS Infra Engineers Pvt. Ltd. under Uttarakhand River Dredging Policy Point no. 10 (2) for 06 months (**annexure no. 3**).
- d) Following that the District Magistrate, Nainital has issued a letter dated 25.03.2022 to Divisional Forest Officer, Haldwani Forest Division authorizing M/s APS Infra Engineers Pvt. Ltd. to collect R.B.M. lying upstream of Nandhour river for a duration of 6 months, under the reference of Disaster Management Act, 2005, and requesting for facilitating demarcation of the requested site (**annexure no. 4**).
- e) In any of the above-mentioned letters, it has not been clearly mentioned about the actual area being proposed for the mining activity. It is only mentioned that the mining will be done in the upstream of Nandhour river.
- f) However, Director, Geology and Mining unit, Directorate of Industry, Dehradun send proposal for mining activity for area in question to

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Secretary, Mining, Government of Uttarakhand vide letter dated December 24, 2021. Wherein, Coordinates of area in question mentioned in the letter as 29° 07'54.4" N, 79° 41'28.0" E. It has also been mentioned that channelization of the river Nandhaur will be done in 1.4 Km length and 40.0 m width of the river (**annexure no. 5**).

- g) In the above-mentioned letter dated December 24, 2021, the area mentioned is reads as "flowing from the mouth of Dehwa river to the mouth of Kailash River near Dubelbera Dhoka forest compound". During the site inspection, Divisional Forest Officer of Haldwani Forest Division has confirmed that the above-mentioned area falls inside the Eco-Sensitive Zone of Nandhaur Wildlife Sanctuary.
- h) Additional Director, Geology and Mining unit, Nainital vide its letter dated March 26, 2022 requested Divisional Forest Officer, Haldwani for joint demarcation of area in question. Divisional Forest Officer, Haldwani vide letter dated March 28, 2022 informed District Magistrate, Nainital that area in question (Upstream part of the river Nandhaur where the mining is being proposed) comes inside the Eco-Sensitive Zone of Nandhaur Wildlife Sanctuary, where the proposed mining activity may cause environmental degradation and loss of bio-diversity and subsequently may attract legal issues (**annexure no. 6**).
- i) There is one mining activity carried out in Nandhaur river as per record available with Mining Department, which is located outside the Nandhaur Wildlife Sanctuary.
- j) It was also confirmed by Divisional Forest Officer, Haldwani Forest Division that the mining activity has been permitted in the downstream of Nandhaur river (approx. 50 m away from the boundary of Eco-Sensitive Zone of Nandhaur Wildlife Sanctuary) to the Uttarakhand Forest Development Corporation for which Environmental Clearance and Forest Clearance have been obtained from MoEF&CC and consent to operate has been granted by Uttarakhand Pollution Control Board. During inspection, mining activity was not carried out due to monsoon season.
- k) As per the point no. 5 of the notification of Eco-Sensitive Zone of Nandhaur Wildlife Sanctuary (Dated 22 May 2020), a monitoring committee has been constituted by the MoEF&CC for monitoring the Eco-Sensitive Zone, where the District Magistrate Nainital has been

designated as the chairman of the committee. The same has been communicated to the District Magistrate Nainital by the Divisional Forest Officer, Haldwani Forest Division vide letter dated March 28, 2022(annexure no. 7).

- l) In a similar matter (WPPIL No. 48 of 2022 at Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital) keeping in the view of the observations made by the National Green Tribunal, Southern Zone, Chennai in O.A. No. 75 of 2020 (SZ) on 19-04-2022, in the matter of Tribunal on its own motion vs. Chief Secretary of Kerala, appearing at Page No. 70 of the order, vide Clause (v), Hon'ble High Court order present reads as "we, hereby, permit dredging of river Nandhaur, but we prohibit the removal of any riverbed material (RBM) from the river for any purpose, whatsoever. The same may be kept on the banks of the river, or in the nearby forest". However, it is to mention that the above-mentioned WPPIL is under subjudice (annexure no. 8).
- m) No mining activity was found on the day of inspection by the joint inspection committee as constituted by NGT. However, it was also observed that some dredging activity including Channelization of Nandhaur river has been performed at two locations with length approx. 100 mtr each. As informed by the Divisional Forest Officer of Haldwani Forest Division, the Channelization of river work has been performed jointly by the Irrigation Department and Forest Department of Uttarakhand in June, 2022. It was also informed that the extracted RBM has been deposited on both the sides of the river.
- n) It is informed by Divisional Forest Officer and Geo-chemist that no mining activity has been started by M/s APS Infra Engineers Pvt. Ltd. at area in question.

Conclusion and Recommendation:

- 1) It is evident from above observation that mining permission has been granted by Secretary (Industrial Development (Mining), Section -1, Uttarakhand Government, which is not started. The area in question is rich in bio-diversity and comes within Eco-Sensitive Zone of Nandhaur Wildlife Sanctuary. Hence, mining activity may not be permitted. However, preventive measures may be taken as per law/rule to protect soil erosion.

[Handwritten signatures and initials]

- 2) District Survey Report of District Nainital has been prepared on 25.07.2018 which need to be updated along with Geo coordinates and fresh replenishment study as per the guidelines of MoEF&CC, Govt. of India.

B. Upper-stream part of Sharda Barrage, Tanakpur, Champawat, Uttarakhand

Salient Observations:

- a) Sharda river is originated from kalapani in the Pithoragarh District, Uttarakhand. It travels approx. 350 km and finally meets with river Ghaghara (U.P).
- b) There is only one mining activity being carried out in Sharda River (approx. 500 m downstream of Sharda Barrage) as per record available with Mining Department. The said mining activity is carried out by Uttarakhand Forest Development Corporation (UKFDC) for which Environmental Clearance (EC) and Consolidated Consent to operate and Authorization (CCA) of UKPCB for 384.69 Hectare covering both upstream and downstream of Sharda barrage.
- c) However, as per condition no. 4 of Forest Clearance (FC) issued on 11.02.2013," no collection of mining shall be permitted from the portion of Sharda River located on upstream of sharda barrage." Following that, UKFDC is carrying out manual mining only on downstream area of approx. 284 hectares and leaving 100 hectares on upstream of Sharda barrage untouched. Copy of EC, FC and CCA is annexed as annexure **no. 9**.
- d) It is also informed by Divisional Forest Officer that upstream of Sharda barrage falls under elephant Corridor.
- e) It is also informed by mining officer, Champawat no mining activity is permitted on the upstream of Sharda barrage by mining department. During visit, no mining activity was observed.
- f) District Magistrate, Champawat has constituted a committee on 05.04.2022 (annexure no. 3 of applicant's letter filed at Hon'ble NGT) for joint inspection and recommendation for flood control.

- g) Based on site inspection and recommendation by the joint committee, District Magistrate, Champawat has issued order on 19.04.2022 for:
- i. First of all, the work of channelization should be done as such a place where more effective solutions can be found by doing channelization. After seeing its effect, it would be appropriate to do channelization work at other places. The channelization work of areas near Gandakhali.No-01 should be done before the monsoon period in 2022 and after assessing its effect in the coming rainy season, advance action should be taken.
 - ii. Addition to above, flood protection work should be done from Boom to Sharda.
 - iii. The above-mentioned work was decided to be done by the Irrigation department, Lohaghat under the supervision of D.F.O, Haldwani division.
- o) It was informed by Divisional Forest Officer, Haldwani that Irrigation Department has made channelization of length approx. 800 m on the upstream of Sharda barrage (approx. 06 km north of barrage) in June, 2022 in compliance of District Magistrate, Champawat order dated 19.04.2022(**annexure no. 10**).

Conclusion and Recommendation:

- 1) It is evident from above observation that no mining activity is being carried out on upstream of Sharda barrage.
- 2) District Survey Report of District Champawat has been prepared on 25.11.2018 which need to be updated along with Geo coordinates and fresh replenishment study as per MoEF & CC, Govt. of India guidelines.
- 3) As informed by the mining officer, Champawat, a short-term permit was issued to Pvt miner. (M/s Shiv Shakti Traders) on 06.03.2021 by Sub-Divisional Magistrate, Purnagiri, Tanakpur on the upstream of sharda barrage, which may be consider as a commercial activity and may not be permitted. *No mining activity has been undertaken so far.*



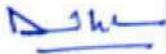
(Deep Chandra Arya)
Conservator of
Forests, Western Circle,
Haldwani.



(Dr. Krishnendu Mondal)
Dy. Director
MoEF&CC, Dehradun.



(Runa Oraon)
Scientist D,
CPCB, Lucknow.



(Dr. D.K. Joshi)
Regional Officer
UKPCB, Haldwani.



(Manish Singh)
Sub Divisional
Magistrate, Haldwani.



(Madan Kishore)
Geo Chemist,
Geology and Mining,
Unit- Haldwani



(Ravi Negi)
Mining Officer,
Geology and Mining, Unit-
Champawat (Representative of
District Magistrate Champawat).

Item No.04

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH**

(By Video Conferencing)

Original Application No.429/2022

Ridhima Pandey

...Applicant

Versus

State of Uttarakhand

...Respondent

Date of hearing: 18.07.2022

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER****Application is registered based on a Letter Petition received by E-mail.****ORDER**

1. Ms. Ridhima Pandey, aged about 14 Years, claiming herself to be a global climate activist working for protection of environment and forests since 2017 when she was 9 years old, has sent the present letter petition, which has been treated and registered as Original Application, complaining about illegal mining inside the reserved forest of Haldwani Forest Division of Uttarakhand.

2. The applicant has submitted that Nandhaur Wildlife Sanctuary is situated in the Haldwani Forest Division. The area surrounding Nandhaur Wildlife Sanctuary has been notified as an Eco-sensitive Zone. The upstream part of Nandhaur River falls under this Eco-sensitive zone. Uttarakhand Government Industrial Development Department (Mining) - Section 1 vide their letter dated 07.01.2022 and District Magistrate, Nainital, vide his order dated 25.03.2022 have authorized M/s. A.P.S Infra Engineers Pvt. Ltd. to collect R.B.M. lying in the Eco-sensitive zone of the Nandhaur river for a duration of 6 months, under the guise of Disaster Management Act, 2005. D.M Champawat has also started the process of permitting the

O. A. No. 429/2022

Ridhima Pandey Vs. State of Uttarakhand

-2-

collection of R.B.M. from the Upper-stream part of Sharda Barrage, Tanakpur, vide order dated 05.04.2022 under the guise of Disaster Management Act, 2005. Haldwani Forest Division and concerned areas of both the rivers Nandhaur and Sharda are rich bio-diversity area and important Schedule-I wildlife habitat and Eco sensitive zone. If it is necessary to remove R.B.M., then permission should be granted after taking expert opinion and removed R.B.M. should be deposited on both the sides of river bank. If the mining activities are allowed in the above forest area then there would be a big loss of environment and wild life habitat because the road construction for mining vehicles, JCB, poclain machine and the labourers to enter in the forest area would not only disturb the wildlife but also destroy their habitat.

3. We appreciate the initiative taken by the applicant for sending the letter petition to this Tribunal bringing to its notice environmental problems of the fragile area of the Himalayas for appropriate directions. Active participation with awareness of the environmental problems and sincere concern for resolution thereof is what is required on the part of all citizens who are under a fundamental duty under Article 51-A (g) of the Constitution of India to protect and improve the environment.

4. In view of the grievances made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof in case of violation of environmental norms. We accordingly constitute Joint Committee of Regional Office of ⁽²⁾ MoEF & CC at Dehradun, ⁽²⁾ Principal Chief Conservator of Forests, ⁽³⁾ Government of Uttarakhand, ⁽⁴⁾ CPCB, ⁽⁵⁾ State PCB, SEIAA, Uttarakhand and ⁽⁶⁾ District Magistrates, ⁽²⁾ Champawat and Nainital and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite

O. A. No. 429/2022

Ridhima Pandey Vs. State of Uttarakhand

-3-

action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for further consideration on 15.11.2022.

A copy of this order, along with a copy of the application and documents enclosed therewith, be forwarded to the Regional Office of MoEF & CC at Dehradun, Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand, CPCB, State PCB, SEIAA, Uttarakhand and District Magistrates, Champawat and Nainital by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 18, 2022
Original Application No. 429/2022
AG

2	बकरीयाल की पत्ती (निकटतम ग्राम)		15.741	145.144	उत्तर-बकरीयाल सिविल वन, दक्षिण - मतीअवझ 2, पूर्व - मतीअवझ 3, पश्चिम- वडम
		कुल	15.741	195.184	

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट वृत्तियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोत वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2020

S.O. 1616(E).— In supersession of Ministry's draft notification S.O. 3882 (E), dated 13th December, 2017, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public:

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indra Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Nandhaur Wildlife Sanctuary is located in two districts namely, Nainital and Champawat districts of Uttarakhand, which derives its name from Nandhaur valley and Nandhaur river which flows inside the valley and the Nandhaur Wildlife Sanctuary lies between North latitudes 28°56'29.35" to 29°16'39.79" and between East longitudes 79°33'3.82" to 80°10'0.03" and spread over an area of 269.95 square kilometers;

AND WHEREAS, this large landscape is flanked by river Yamuna towards the west to river Bhagmati in Nepal towards east;

AND WHEREAS, this landscape is a representative of Tarai-Duar Savana Eco-region, flanking the Himalayas in the southern slopes and the whole area of the landscape is recognized as an important center of biodiversity, both at national and global level;

AND WHEREAS, major flora available in the Sanctuary are *Cassia fistula* (amaltash), *Ailanthus excelsa* (aru), *Mangifera indica* (aam), *Spondias pinnata* (aamra), *Emblica officinalis* (aavala), *Wrightia tomentosa* (indrajao), *Tamarindus indica* (emli), *Sterculia villosa* (udal), *Bauhinia variegata* (kachmar), *Flacourtia indica* (katail [kandaii]), *Zizyphus xyloyna* (kathber), *Haplohragma adenophyllum* (kath sagaon), *Marica sapida* (kafal), *Buchanania lanzan* (kathbhilava), *Buchanania latifolia* (pyalcharoji), *Gmelina arborea* (kamhar [gamhar]), *Albizia odoratissima* (kalasiras), *Acacia farnesiana* (kinkar), *Careya arborea* (kumbhi), *Ficus cunia* (kumiya), *Schleichera oleosa* (kusum), *Holarrhena antidysenterica* (kuda), *Phoebe lanceolata* (kakra), *Muchilus odoratissima* (kaola), *Holoptelea integrifolia* (kanju), *Celtis tetrandra* (kharik), *Bauhinia malabarica* (khatava), *Beridelia retusa* (khaza), *Ficus infectoria*, *Ficus rumphii* (khabar pakar), *Sapium insigne* (kheena), *Acacia Catechu* (kher), *Bauhinia purpurea* (kherwall), *Trewia nudiflora* (kutel), *Ficus racemosa* (gular), *Boehmeria rugulosa* (gethi), *Bridelia ratusa* (goli [ekdanya]), *Ehretia laevis* (chamror [ichoda]), *Casearia elliptica* (chilla), *Wendlandia exserta* (chila [tirchunya]), *Diploknema butyracea* (chura), *Pinus roxburghii* (chir), *Alstonia Scholaris* (chitvan [chiun]), *Syzygium cumini* (jamun), *Trema orientalis* (jeevanti), *Putranjiva roxburghii* (jooti), *Tamarix dioica* (jhau), *Lennea coromandelica* (jhingan), *Cinnamomum tamala* (dalchini [trjpatta]), *Garuga pinnata* (titmira [kharpat]), *Miliusa velutina* (domsaal), *Butea monosperma* (dhak), *Elaeotendron glaucum* (dhibri), *Sapium sebiferum* (tarcharbi), *Oroxylum indicum* (tarloo [tasriya]), *Cocculus laurifolius* (tilfora), *Ficus roxburghii* (timla), *Toona ciliata*, *Cedrela toona* (tun), *Diospyros tomentosa* (tandu), *Gardenia turgida* (thanela), *Grewia elastica* (thaman), *Woodfordia fruticosa* (dhaula), *Erythrina suberosa* (dhauladhak), *Lagerstroemia parviflora* (dhor), *Azadirachta indica* (neem), *Stereospermum suaveolens* (padal), *Bischofia javanica* (panisemal), *Dalbergia lonceolaria* (passi [bandhar]), *Ficus religiosa* (pipal), *Kydia calycina* (pula [patta]), *Broussonetia papyrifera* (paper malvari), *Mitragyna pravifolia* (faldu), *Grewia hainesina* (farasen), *Acacia nilotica* (babool), *Terminalia helleborica* (bahera), *Melia azedarach* (bakem), *Crataeva religiosa* (barna [baruna]), *Ficus bengalensis* (banratha [bargad]), *Anogeissus latifolia* (baakali), *Pterocarpus marsupium* (bijaysaal), *Ficus scandens* (betuli), *Rhododendron arboreum* (burash), *Quercus leucotrichophora* (baanj), *Aegle marmelos* (bel), *Zizyphus mauritiana*, *Zizyphus jujuba* (ber), *Hymenodictyon excelsum* (borang), *Semecarpus anacardium* (bhilava), *Grewia oppositifolia* (bhimal), *Madhuca indica* (mahuva), *Zizyphus xyloyna* (makida), *Litsea glutinosa* (maida), *Randia dumetorum* (maninfall), *Eucalyptus hybrid* (eucalyptus [safeda]), *Mallotus philippensis* (rohani), *Cordia dichotoma*, *Cordia myxa* (lasora), *Casearia graveolens* (lalchila), *Morus alba* (sahtut [tutari]), *Dalbergia sissoo* (shisu [shisam]), *Xylocarpus longifolium* (shallu), *Shorea robusta* (saal), *Ougeinia oojeinensis* (saadan), *Tectona grandis* (saogaon), *Albizia chinensis* (siras [kala]), *Albizia procera* (siris [safed]), *Moringa oleifera* (seazna), *Bombax ceiba* (semal), *Terminalia alata* (sain [ashna]), *Nyctanthes arborvitae* (hersringar), *Adina cordifolia* (haldu), *Terminalia chebula* (harra [harad]), etc;

AND WHEREAS, among the mega-fauna found in this region, the most important ones are tigers, elephants, leopards, sloth bears, and numerous herbivores and the diverse fauna of this area enjoys equally diverse floral diversity, which can be estimated considering the fact that the area has twenty-seven types and sub-types of Champion and Seth classified forests;

AND WHEREAS, the fauna recorded from the Nandhaur Wildlife Sanctuary are Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), common langur (*Presbytis entellus*), jungle cat (*Felis chaus*), tiger (*Panthera tigris*), common mongoose (*Hertestes edwardsi*), small indian mongoose (*Hertestes auropunctatus*), jackal (*Canis aureus*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), sloth bear (*Melursus ursinus*), small Indian civet (*Everriecula indica*), blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), spotted deer (*Axis axis*).

sambhar (*Cervus unicolor*), wild pig (*Sus scrofa*), five striped palm squirrel (*Funambulus pannanti*), Indian field mouse (*Musbooduga*), common house rat (*Rattus rattus*), house mouse (*Mus musculus*), porcupine (*Hystrix indica*), the grey musk shrew (*Suncus murinus*), Rufoustailed hare (*Lepus nigricollis ruficaudatus*), flying fox (*Pteropus giganteus*), fruit bat (*Rousettus leschenaulti*), goral (*Naemorhedus goral*), Indian pangolin (*Manis cresichodata*), Asian elephant (*Elephas maximus*), common palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), red giant flying squirrel (*Petaurista petaurista*), hispid hare (*Caprolagus hiseldus*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), serow (*Capricornis sumatraensis*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nandhaur Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.7 kilometres to 15.0 kilometres around the boundary of Nandhaur Wildlife Sanctuary, in Nainital and Champawat districts in the State of Uttarakhand as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.7 kilometres to 15.0 kilometres around the boundary of Nandhaur Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 540.267 square kilometres. The detail area of the Eco-sensitive Zone are given as:

Haldwani Forest Division	: 270.175 square kilometers;
Champawat Forest Division	: 100.880 square kilometers;
Tarai East Forest Division	: 167.103 square kilometers;
Revenue Area of 2 villages	: 1,9518 square kilometers;
Van panchayat area	: 0.1574 square kilometers.

- (2) The boundary description of Nandhaur Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Nandhaur Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID and Annexure-IIIE**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Nandhaur Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure III**.
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IVA and Annexure-IVB**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;

- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj; and
- (xi) Public Works Department.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the State Government.**— The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:—

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**— Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.**— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.



- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.-** Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic	Taking measures of mitigation as per the applicable

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	amenities.	laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.— For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Collector, Nainital	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Collector of Champawat	Member;
(iii)	Representative of the Department of Environment, Government of Uttarakhand	Member;
(iv)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Uttarakhand	Member;
(v)	Regional officer, Uttarakhand State Pollution Control Board	Member;
(vi)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	One expert in the area of ecology & environment to be nominated by the State Government for a term of one year in each case	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Haldwani Forest Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/113/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE UTTARKHAND

East Side - Sarda North 22,23, Mathiabanjh 3,4, Chhini 53, West Bastia 1,2,3, East Bastia 1,2,3,4, Naghan 8, Baramdeo A2,A1, Kakrali B, A, D, North Guliapani 4b, South Guliapani 1,2,3, East Kilpura A, B, C;

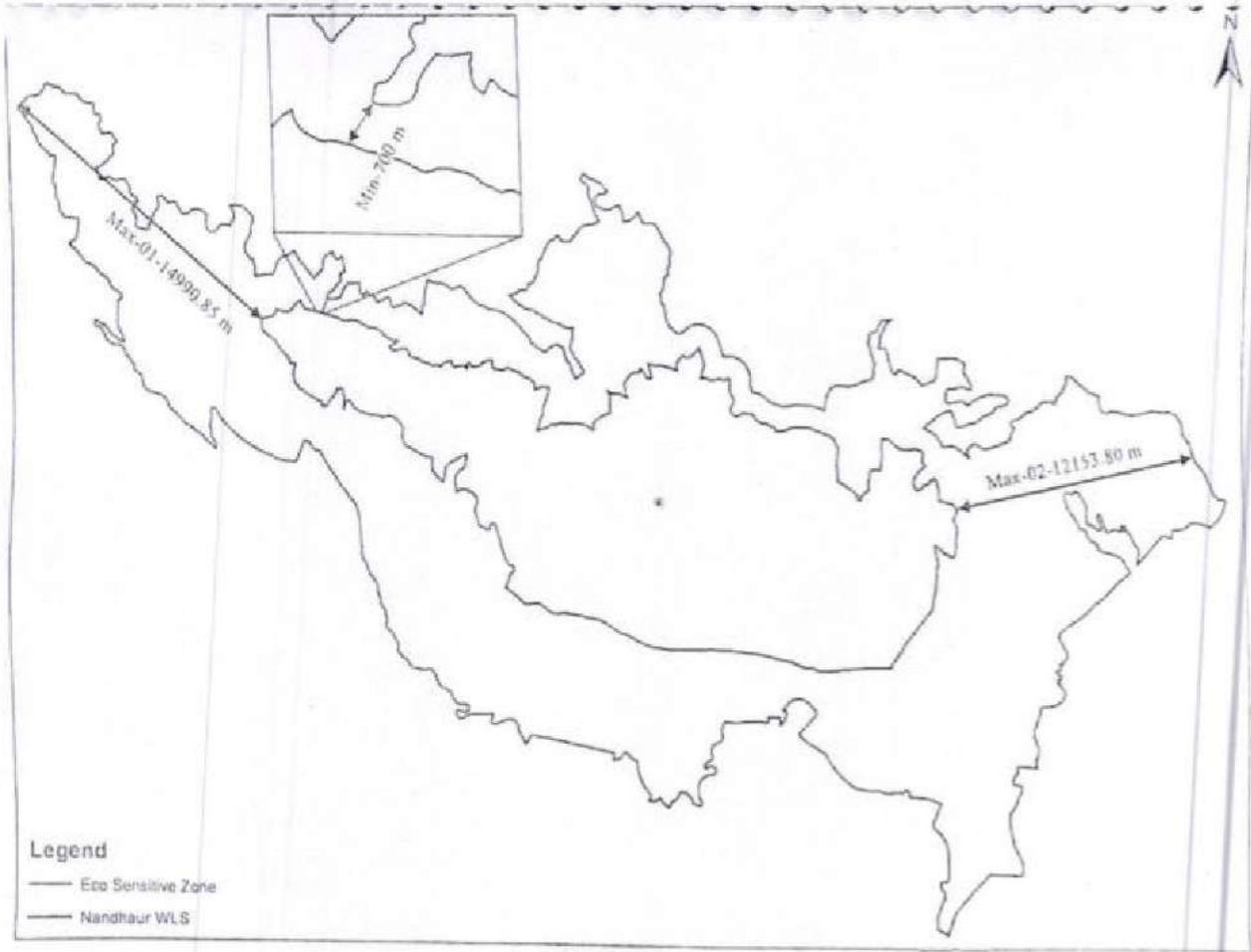
West Side - Kalega-6,1, Nandhour-1 Sumanthapla-2, Lakhanmandi-5a, 4c, 4a,4b,3,2a,1a,8b, Dolpokhara- 5, 8b, 8c, 8a, 7a, 7b, 6b, 6a, Kalukhera- 5,6,3 Ratighat- 3a, 1a, 1b, 2b, 2a, 3b, 3a,4, 5, 6a, 6b Garhkharak block c.no.-1, 2, 3, 4, 5a, 5b Simlia block c.no.-5b, 4c, 4a, 3, 2, 1 Patrani block c.no.- 4, West Lobchula 1a, 2b, 2a, 3a,4a;

North Side - East Lobchula 1,2,3, Gauniyaroa 1,13, North Kholgarh 1, Upraula Gauniyaroa 1,2, South Loweranala 1,4,5, North Loweranala 4b, 3b, 2b Kundal 1,4,5,8 Aaligarh 1b, 1a, Betlad 5a, 5b (part),2a(part),1a(part),1b(part), Durgapipal 11(part), Sarda North 4(part),5(part),6(part);

South Side - North Banbasa Block 5,8,7, West Kilpura A, Dogari block-1 & 2, Sudlimath Block I, 11b, Sudlimath Block-II-2b,2a,1b,1a, Beda Reserve -3 East Jaulasal- 16,15,14,13,12, West Jaulasal- 6b, Hanspur block-C, Kalega-7

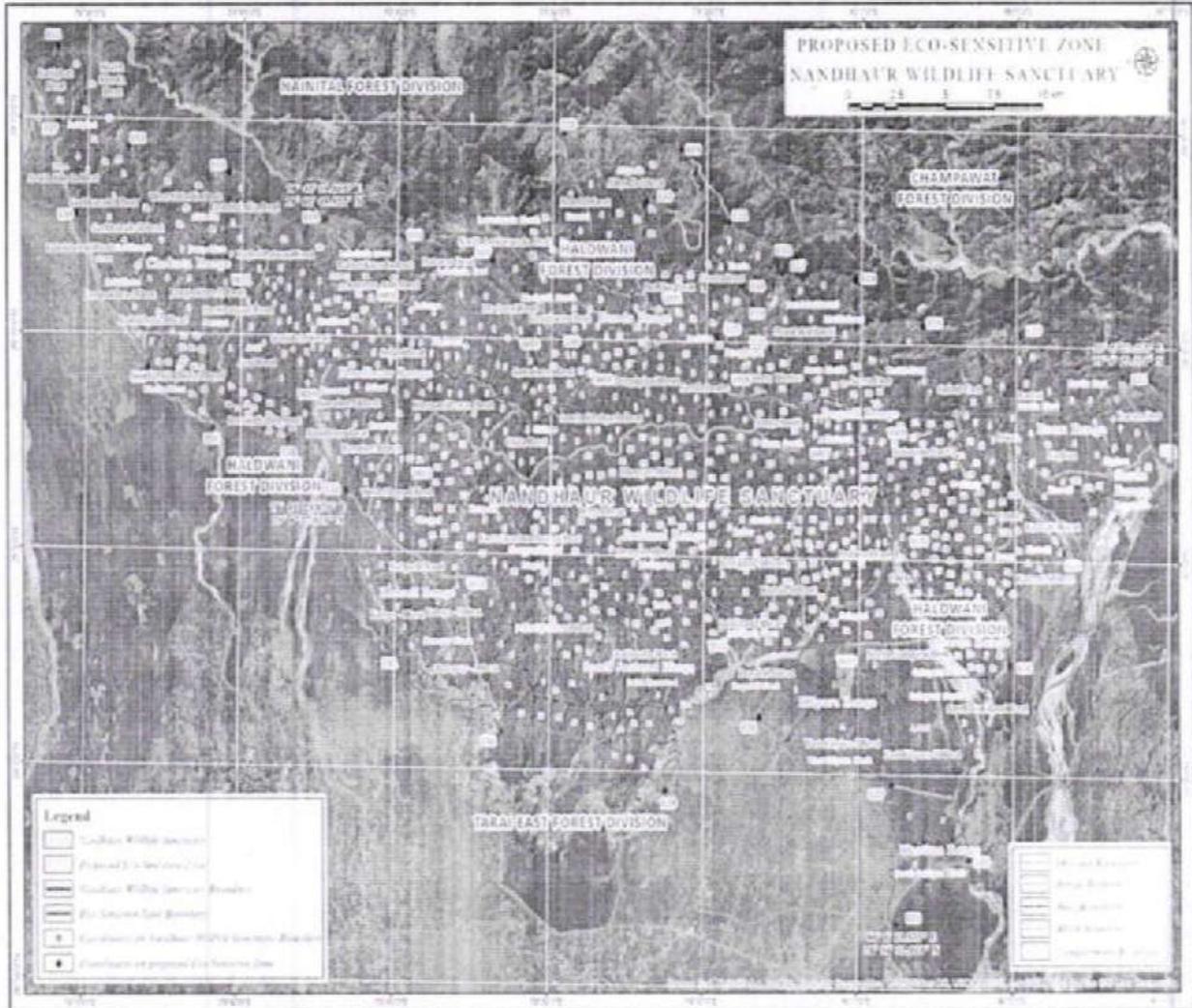
ANNEXURE- IIA

MAP OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



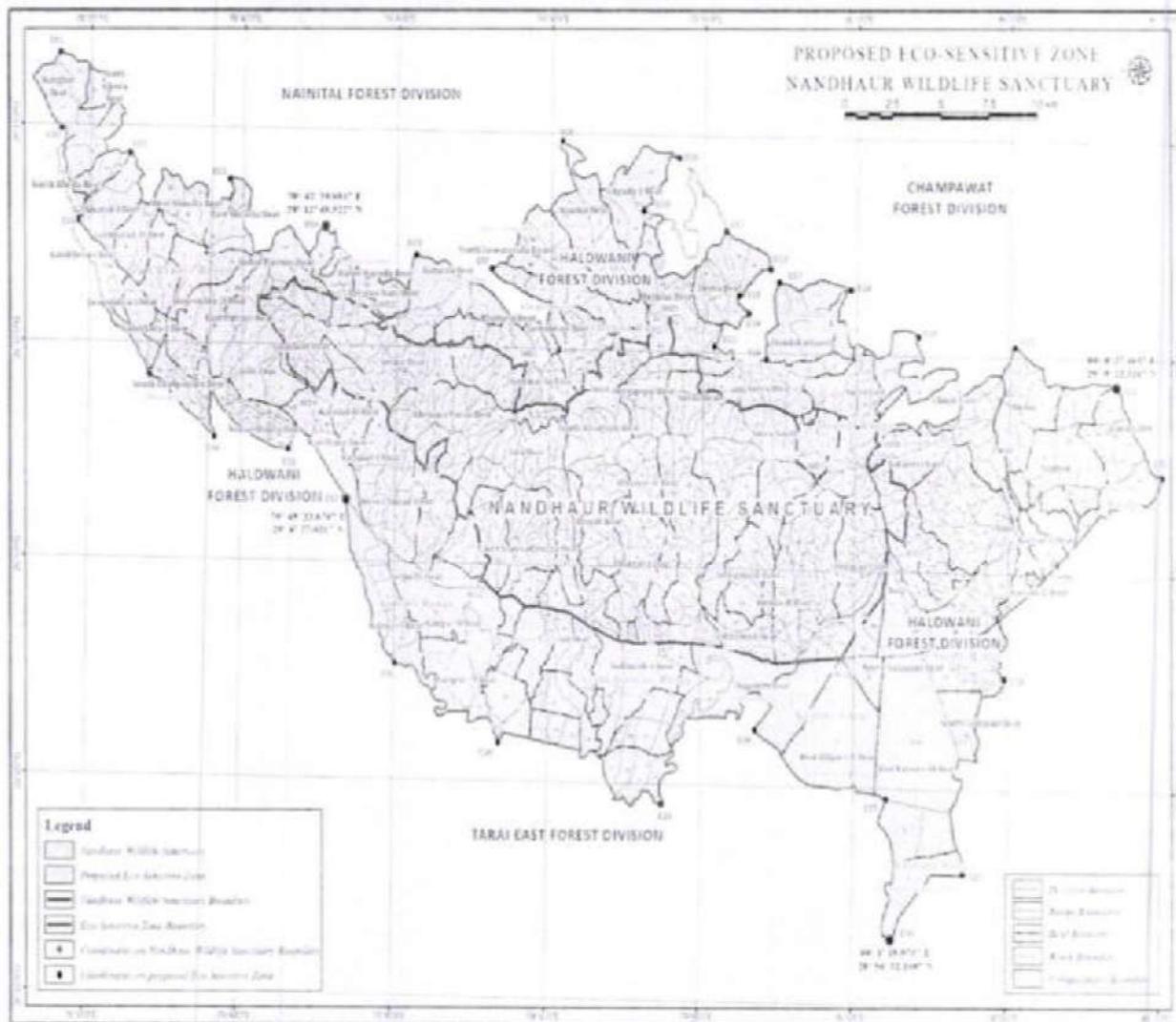
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



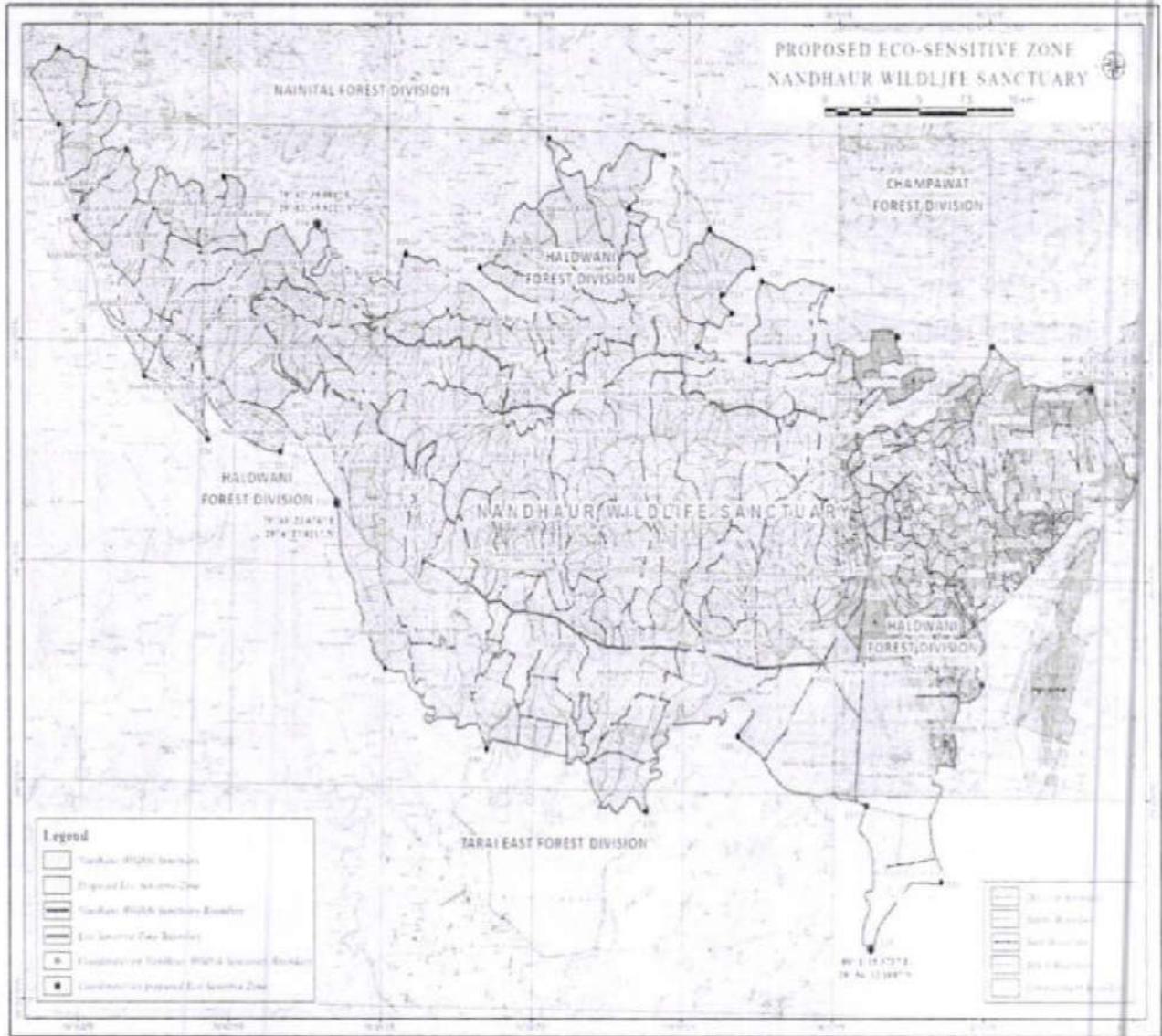
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



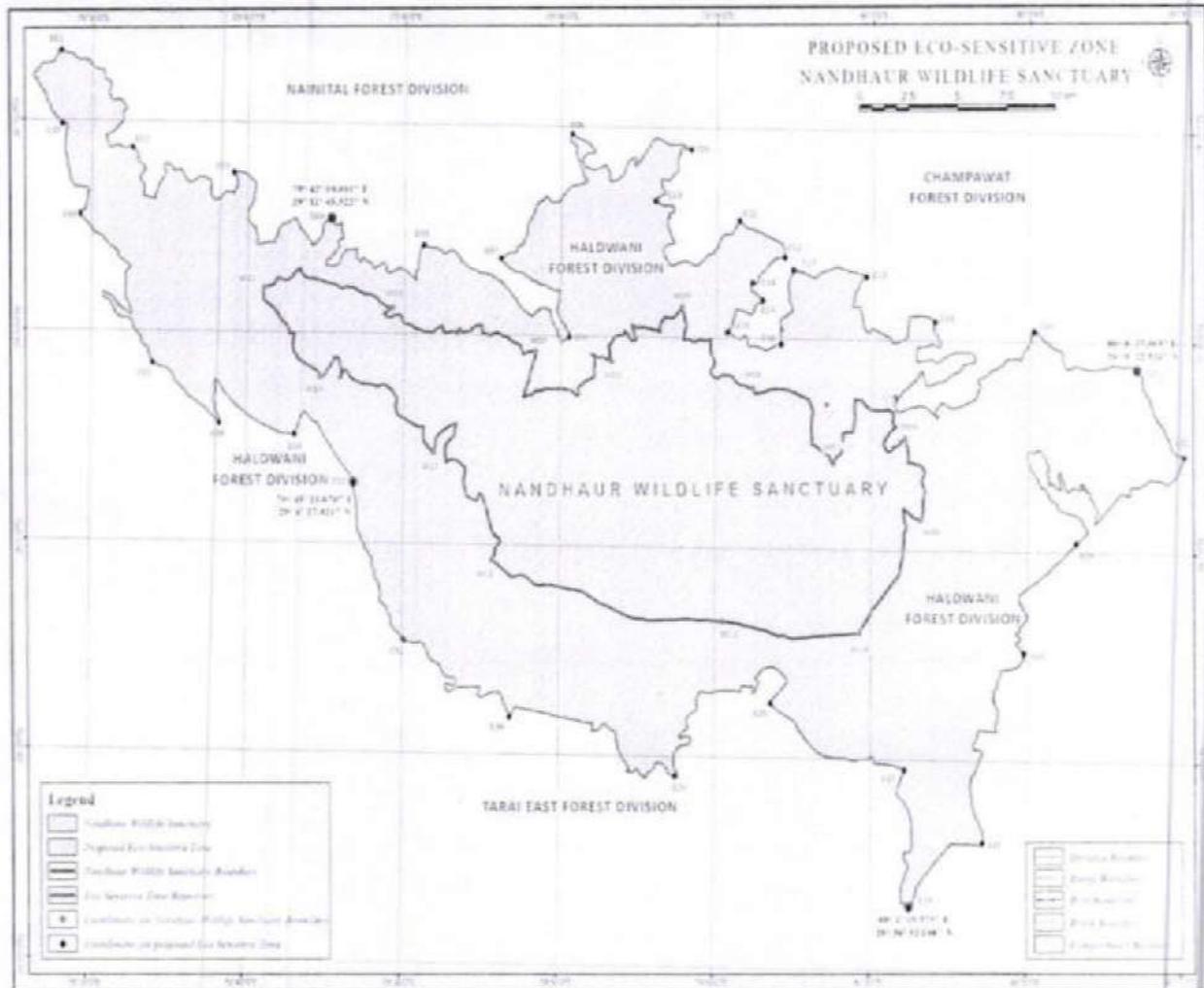
ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

MAP OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY

Point	Longitude	Latitude	Description
W01	79° 40' 31.695" E	29° 11' 3.884" N	Nandhaur WLS
W02	79° 44' 37.284" E	29° 10' 38.038" N	Nandhaur WLS
W03	79° 49' 12.193" E	29° 9' 37.718" N	Nandhaur WLS
W04	79° 51' 38.832" E	29° 9' 25.676" N	Nandhaur WLS
W05	79° 53' 53.049" E	29° 10' 44.254" N	Nandhaur WLS
W06	79° 56' 10.269" E	29° 8' 49.470" N	Nandhaur WLS

W07	79° 58' 45.739" E	29° 7' 3.473" N	Nandhaur WLS
W08	80° 1' 2.823" E	29° 7' 40.210" N	Nandhaur WLS
W09	80° 1' 34.977" E	29° 5' 44.964" N	Nandhaur WLS
W10	79° 59' 37.921" E	29° 3' 1.139" N	Nandhaur WLS
W11	79° 55' 15.137" E	29° 3' 15.607" N	Nandhaur WLS
W12	79° 47' 50.944" E	29° 4' 39.597" N	Nandhaur WLS
W13	79° 45' 57.253" E	29° 7' 11.210" N	Nandhaur WLS
W14	79° 42' 19.679" E	29° 8' 57.363" N	Nandhaur WLS

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Point	Longitude	Latitude	Description
E01	79° 33' 57.762" E	29° 16' 39.994" N	Eco Sensitive zone
E02	79° 36' 19.052" E	29° 14' 23.009" N	Eco Sensitive zone
E03	79° 39' 33.453" E	29° 13' 48.082" N	Eco Sensitive zone
E04	79° 42' 39.081" E	29° 12' 45.522" N	Eco Sensitive zone
E05	79° 45' 36.564" E	29° 12' 8.292" N	Eco Sensitive zone
E06	79° 50' 17.169" E	29° 10' 0.514" N	Eco Sensitive zone
E07	79° 48' 4.071" E	29° 11' 51.318" N	Eco Sensitive zone
E08	79° 50' 20.665" E	29° 14' 50.935" N	Eco Sensitive zone
E09	79° 52' 1.722" E	29° 13' 58.015" N	Eco Sensitive zone
E10	79° 53' 13.318" E	29° 11' 2.581" N	Eco Sensitive zone
E11	79° 54' 38.887" E	29° 10' 30.784" N	Eco Sensitive zone
E12	79° 57' 43.191" E	29° 9' 15.266" N	Eco Sensitive zone
E13	79° 59' 48.190" E	29° 11' 30.730" N	Eco Sensitive zone
E14	80° 1' 59.701" E	29° 10' 27.968" N	Eco Sensitive zone
E15	80° 5' 8.790" E	29° 10' 16.371" N	Eco Sensitive zone
E16	80° 8' 27.463" E	29° 9' 22.326" N	Eco Sensitive zone
E17	80° 10' 0.297" E	29° 7' 18.207" N	Eco Sensitive zone
E18	80° 6' 32.886" E	29° 5' 13.986" N	Eco Sensitive zone
E19	80° 4' 52.771" E	29° 2' 35.607" N	Eco Sensitive zone
E20	80° 3' 35.373" E	28° 58' 4.653" N	Eco Sensitive zone
E21	80° 1' 15.573" E	28° 56' 32.108" N	Eco Sensitive zone
E22	80° 1' 4.867" E	28° 59' 46.918" N	Eco Sensitive zone
E23	79° 56' 47.563" E	29° 1' 19.672" N	Eco Sensitive zone

E24	79° 53' 46.660" E	28° 59' 33.923" N	Eco Sensitive zone
E25	79° 48' 26.818" E	29° 0' 54.202" N	Eco Sensitive zone
E26	79° 45' 2.150" E	29° 2' 42.193" N	Eco Sensitive zone
E27	79° 43' 23.870" E	29° 6' 27.021" N	Eco Sensitive zone
E28	79° 41' 31.539" E	29° 7' 34.821" N	Eco Sensitive zone
E29	79° 39' 7.687" E	29° 7' 49.656" N	Eco Sensitive zone
E30	79° 36' 59.523" E	29° 9' 14.706" N	Eco Sensitive zone
E31	79° 34' 35.786" E	29° 12' 46.539" N	Eco Sensitive zone
E32	79° 34' 0.471" E	29° 14' 55.206" N	Eco Sensitive zone

ANNEXURE-IVA

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Name	Village	Longitude	Latitude
Kathaul	V1	79° 58' 32.561" E	29° 8' 27.937" N
BakrialukiPatli	V2	80° 0' 44.337" E	29° 8' 39.672" N

ANNEXURE-IVB

DETAILS OF THE VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG REVENUE AREA AND BOUNDARY DESCRIPTION

S. No.	Name of Village	Tehsil	Area of Panchayati Van inside the Village (Ha.)	Area of Revenue Village (Ha.)	Boundary
1	Kathoul	Purnagiri	-	50.040	North – North Sarda 16, South – Kathoul 1 & 2, East – Kathoul 3, West-South Sarda 13
2	Bakriyal ki Pati (Nearest Village)		15.741	145.144	North-Bakriyal Civil Forest, South – Mathiyabanj 2, East – Mathiyabanj 3, West Budam
		Total	15.741	195.184	

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

प्रेषक

आर० मीनाश्री सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

आद्योगिक विकास (जनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 07 जनवरी, 2022

विषय: उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु सं० 10(2) के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत ठेकेदारों को रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निर्देशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-8932/खनन/भू०खनि०ई०/रे०वि०नि०-रि०दे०/2021-22, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 72 में निहित प्रावधान का समस्त अधिनियमों, विधियों आदि पर अव्यवहारी प्रभाव होने के कारण उत्तराखण्ड शासन स्तर पर सायक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपरोक्त प्रावधानों, विधियों या अधिनियमों से असंगत होते हुए भी प्रभावी होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु सं० 10(2) के प्रावधानानुसार ड्रेजिंग कार्य हेतु नदी के समुचित चैनलाइजेशन, नदी के बहाव को सुव्यवस्थित करने तथा आस-पास के गाँव/क्षेत्रों में बाढ़ व जनहानि से बचाव आदि के दृष्टिगत जनपद नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के अग्र नन्धीर घोरगलिष क्षेत्र (अग्र नन्धीर नदी) में जमा मलवा/आर०वी०एम० की निकासी एन०एच० 87 के निर्माण कार्य हेतु ए०पी०एस० इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा०लि० के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने तथा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु सं० 11 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 33 के अन्तर्गत नियम 34 को शिथिल करते हुए इस कार्य हेतु जमा आर०वी०एम० की मात्रा पर (आर०वी०एम०) अनुरोधित अन्य दाय धनराशि को 06 समान किशों में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली अनुज्ञा के क्रम में ए०पी०एस० इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा०लि० द्वारा निकाली किये जाने वाले मलवा आर०वी०एम० की आपूर्ति एन०एच० निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्षेत्र को करते हुए तयार माल का उपयोग संबंधित इकाई द्वारा एन०एच० 87 के निर्माण कार्य हेतु किया जायेगा। ए०पी०एस० इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा०लि० के पक्ष में एन०एच० 87 के निर्माण कार्य हेतु दी जा रही अनुज्ञा अनुमति मात्र एन०एच० परियोजना कार्य हेतु ही प्रदत्त की जा रही है, संबंधित कार्यदायी इकाई द्वारा किसी भी दशा में इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जिला अधिकारी

17/01/2022

ABUFLV/96
Sema...
SRJ

भवदीय

(आर० मीनाश्री सुन्दरम)
सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1418 / 30-जी.सी./ 2021-22

दिनांक : 25 मार्च, 2022

विषय : उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के अनुसार राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत ठेकेदारों को रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुकूल के सम्बन्ध में।

प्रभागीय जनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग,
हल्द्वानी।

रूपमा उपरोक्त विषयक औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2370/VII-A-1/2022/5(120)/21 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 72 में निहित प्रावधान का समस्त अधिनियमों, विधियों आदि पर अध्यारोही प्रभाव होने के फलस्वरूप शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबन्ध अन्य किसी विधि या अधिनियम से असंगत होते हुए भी प्रभावी होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के प्रावधानानुसार ड्रेजिंग कार्य हेतु नदी के समुचित बैनलाईजेशन, नदी के बहाव को सुव्यवस्थित करने तथा आस-पास के गाँव/क्षेत्रों में बाढ़ व जनहानि से बचाव आदि के दृष्टिगत जनपद नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धीर चौरगलिया क्षेत्र (अपर नन्धीर नदी) में जमा मलवा/आर.बी.एम. की निकासी एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. के पक्ष में 08 नह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने तथा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 11 एवम् उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-68 के अन्तर्गत नियम 54 को शिथिल करते हुए इत कार्य हेतु जमा आर.बी.एम. की मात्रा पर देय सैंपल्टी की धनराशि व अन्य देय धनराशि को 08 सनान किशतों में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तमानुसार स्वीकृत की जाने वाली अनुज्ञा के क्रम में ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. द्वारा निकासी किये जाने वाले मलवा, आर.बी.एम. की आपूर्ति एन.एच. निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्रेशर को करते हुए तैयार माल का उपयोग संबंधित इकाई द्वारा एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु किया जायेगा। ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. के पक्ष में एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु दी जा रही अनुज्ञा अनुमति मात्र एन.एच. परियोजना कार्य हेतु प्रदत्त की जा रही है, संबंधित कार्यदायी इकाई द्वारा किसी भी दशा में इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

उत्तके अतिरिक्त औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2372/VII-A-1/2022/5(120)/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि "आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-72 द्वारा प्राविधानित उपबन्ध के अन्य किसी विधि या अधिनियम से असंगत होते हुए भी प्रभावी होने के दृष्टिगत राज्य की नदी/जलाशय/नहरों में भारी मात्रा में जमा मलवा/आरबीएम/सिल्ट वाले ऐसे क्षेत्र/भू-भाग, जिससे भू-कटाव, बाढ़ एवम् जान-माल का खतरा होने की प्रबल संभावना बनी रहती हो, से मलवा/आरबीएम/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 8 "रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा स्वीकृति" के प्रावधानानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में जिलाधिकारी को प्रदत्त अधिकारी के अन्तर्गत जान-माल की सुरक्षा, नदी के बहाव व संरक्षण, नदी के व्यापक बैनलाईजेशन तथा आस-पास के समीपवर्ती गाँव/क्षेत्रों में बाढ़ व जनहानि को रोके जाने हेतु ऐसे क्षेत्र/भू-भाग में ड्रेजिंग कार्य के माध्यम से नदी में जमा मलवा/आरबीएम/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किए जाने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी पूर्ण रूप से अधिकृत होंगे, जिन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-72 में निहित अध्यारोही प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर वन विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।" तदक्रम में इत कार्यालय के पत्र संख्या 1865/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 24 जनवरी, 2022 द्वारा शारान के उक्त निर्देशों के अनुपालन में अग्रतार कार्यवाही हेतु समस्त प्रभागीय जनाधिकारी, जनपद नैनीताल को सम्बोधित पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में अपर निर्देशक, भूखनन एवम् खनिज इकाई, जनपद नैनीताल को सम्बोधित तथा, इस कार्यालय को पृष्ठविना आपकी कार्यालय पत्र संख्या 1461/9-2(1) क्रमशः-2

(2)

हल्द्वानी, दिनांक 28.01.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय का उक्त उल्लिखित पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है तथा एन.एच.-87 के निर्माण कार्य हेतु मै. ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है, तो यह कार्य उक्त परिधि में नहीं आता है। यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र नन्धौर वन्यजीव अभ्यारण के इको सेंसिटिव जोन का भाग है, जो भारत सरकार पर्यावरण वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2020 से नोटिफाईड है, जिस कारण सीमांकन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 29 जनवरी, 2022 में इस आपके वन प्रभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः शासन के पत्र संख्या 2372/VII-A-1/2022/5(120)/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1865/30-जी.सी./2021-22 दिनांक 24 जनवरी, 2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण में नियमानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

LRJ
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

संख्या एवम् दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वन एवम् पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

/_____
जिलाधिकारी,
नैनीताल

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
खनन,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 3932/खनन/भूखनि0ई0/रोवि0नि0-रि0ट्रे0/2021-22.

दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

विषय:

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10 (2) के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत ठेकेदारों को रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ए0पी0एस0 इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा0लि0, डी-138, सेक्टर-51, नोयडा, उत्तराखण्ड (वर्तमान पता-मोटा हल्द्वी रिलाइन्स पम्प के सामने, हल्द्वानी, नैनीताल) के द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर चौर गलिया क्षेत्र (अपर नन्धौर नदी) में उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के प्रावधानान्तर्गत उपखनिजों के चुगान की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2021 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न नोटरीज्ड शपथ पत्र संख्या IN-DL532931758922550, दिनांक 26 मई, 2016 प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा एन0एच-87 में निर्माण कार्य किये जाने हेतु सदभाव नैनीताल हाईवे प्राईवेट लिमिटेड को अनुबन्धित किया गया है तथा सदभाव नैनीताल हाईवे प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा उक्त कार्य हेतु ए0पी0एस0 इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा0लि0 अधिकृत किया गया है। सदभाव नैनीताल हाईवे प्राईवेट लिमिटेड के पत्र संख्या SEL/RK-2/FY 21-22/WO/AIEPL/001655, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित है कि "With reference to the discussions had between, **Sadbhav Engineering Limited** (hereinafter referred to as "SEL") and **M/s APS Infra Engineers Private Limited** (hereinafter referred to as "M/s" APS Infra"), we are pleased to award you the balance Construction works of Highway, Structures and Other works as instructed by SEL representative in the Project stretch of "Four Laning of Rampur-Kathgodam Section of NH-87 from Design Chainage 43.446 KM (Existing Ch. 42/791KM) to Design Chainage 93.226 KM (Existing Chainage 88/000 KM) (Package-II) in the State of Uttarakhand under NHDP Phase III" under the terms and Conditions stated in this work Order".

उपरोक्त वर्णित पत्र के साथ संलग्न प्रश्नगत क्षेत्र की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 15.06.2021 में उल्लिखित है कि "कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या 1316/30-जी0सी0/2020, दिनांक 19 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न, उपरोक्त विषयक श्री भुवन पोखरिया एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र, जिसमें उनके द्वारा अपर नन्धौर नदी में भारी मात्रा में नदी के बीचों बीच जमा मलवे को हटाकर रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत संयुक्त निरीक्षण कर नदी के चैनेलाईज करने का अनुरोध किया गया है। जिसमें कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के पत्र संख्या 206/भूखनि0ई0/रिवर ट्रेनिंग/2021-22, दिनांक 09 जून, 2021 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि को राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा दिनांक 15.06.2021 को श्री भुवन पोखरिया एवं अन्य की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया।

श्री भुवन पोखरिया एवं अन्य के द्वारा मौके पर अवगत कराया गया है कि नन्धौर नदी के पश्चिमी तट पर चौरगलिया कस्बा, खौला बाजार एवं ग्रामीण क्षेत्र निकट स्थित है। स्थल पर नन्धौर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर

प्रवाहित हो रही है। वर्तमान में नदी अत्यधिक मात्रा में उपखनिज (आर०बी०एम०) एकत्रित है। प्रस्तावित चैनेलाईज नदी क्षेत्र के पश्चिमी दिशा की ओर उत्तर से दक्षिणा की ओर टोका वन आवासीय परिसर जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग का विश्राम गृह व वन क्षेत्राधिकारी, नन्धौर रेंज का कार्यालय अवस्थित है। ग्राम दुबेलबेडा, ग्राम खौला बाजार, ग्राम पचौनिया, ग्राम सुनारखेडा, ग्राम तल्ला चोरगलिया, ग्राम आमखेडा, ग्राम कुटलिया, ग्राम मुखानी खडकू, ग्राम घूसापुर व ग्राम बिहारीगढ़ स्थित है। निरीक्षण के समय देखा गया कि नन्धौर नदी द्वारा अपने पश्चिमी किनारे पर स्थित आबादी क्षेत्र आदि स्थानों पर कटान किया गया है तथा नदी द्वारा अपनी मुख्य धारा में अत्यधिक मलवा जमा किया गया है।

सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियन्ता द्वारा मौके पर अवगत कराया गया है कि उपरोक्त स्थल में दिनांक 09.06.21 को सिंचाई विभाग, हल्द्वानी एवं सितारगंज के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अपर सहायक अभियन्ता के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें देवहा नदी के मुहाने से कैलाश नदी के मुहाने दुबेलबेडा ढोका फोरेस्ट कम्पाउंड तक लगभग 1.40 किमी० लम्बाई में ऊपर से बहकर अति विशालकाय बोल्टर, आर०बी०एम० मलवा एकत्रित हो गया है जिसकी वजह से नदी की धारा मुडकर दायी तरफ आबादी क्षेत्र की ओर हो गयी है। जिसमें देवहा नदी के मुहाने से कैलाश नदी के मुहाने दुबेलबेडा ढोका फोरेस्ट कम्पाउंड के पास तक लगभग 1.40 किमी० लम्बाई में नदी के मध्य भाग में जो मलवा/उपखनिज/बोल्टर भर गये हैं को आपदा न्यूनीकरण एवं बाढ़ से बचाव की दशा में रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत जमा मलवा/उपखनिज/बोल्टर हटाकर नन्धौर नदी को उसके मध्य भाग में चैनेलाईज कर दिया जाये एवं साथ ही नन्धौर नदी के दायें पार्श्व में बाढ़ सुरक्षा कार्य करवा दिया जाये, चोरगलिया क्षेत्र के गांवों की आबादी की सुरक्षा एवं नानकमत्ता, सितारगंज क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जलभराव की समस्या का समाधान होना संभव होगा।

वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा मावे पर अवगत कराया गया कि नदी में भारी मात्रा में नदी के बीचों बीच जमा मलवा/उपखनिज/बोल्टर को सक्षम स्तर से अनुमति मिलने के उपरान्त ही हटाया जाना सम्भव होगा। प्रश्नगत क्षेत्र की भौगोलिक कॉर्डिनेट्स निम्नवत है :-

उत्तर में - 29° 07' 54.4", पूरब में - 79° 41' 28.0"

उपरोक्त प्रकरण में सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियन्ता द्वारा मौके पर दिखाये गये स्थल के अनुसार नन्धौर नदी को मुख्य धारा में चैनेलाईजेशन करने हेतु 1.40 किमी० लम्बाई और औसतानुसार 40 मीटर चौड़ाई व औसतानुसार 3.0 मीटर गहराई का चैनल बनाकर मौके पर उपलब्ध/विद्यमान आर०बी०एम०/उपखनिज/बोल्टर को हटाया जाना आवश्यक है, ताकि चोरगलिया क्षेत्र के गांवों की आबादी की सुखा एवं नानकमत्ता, सितारगंज क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जलभराव की समस्या का समाधान हो सके।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1873/VII-A-1/2021-05(28)/2021, दिनांक 10 नम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु 10(2) में प्राविधानित है कि "राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं के निर्माण कार्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से उक्त परियोजनाओं के निकटस्थ नदी तल क्षेत्रों में रिवर ड्रेजिंग हेतु समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में ड्रेजिंग कार्य हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा अनुरोध करने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

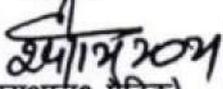
एक ही क्षेत्र हेतु एक से अधिक परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों से अनुरोध प्राप्त होने पर निकटस्थ परियोजना की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों को उक्त क्षेत्र में रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

स्वीकृत क्षेत्र में समिति द्वारा आंकलित उपखनिज मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की मात्रा पर मैदानी क्षेत्र हेतु निर्धारित रायल्टी की दर की दोगुना धनराशि व अन्य देयकों का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्षक में सरकारी

कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों द्वारा जमा किया जायेगा तथा उक्त उपखनिजों का परियोजना के लिए इतर व्यवसायिक उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा'।

अतः उपरोक्त के क्रम में ए0पी0एस0 इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा0लि0, डी-138, सेक्टर-51, नोयडा, उत्तराखण्ड (वर्तमान पता-मोटा हल्दू रिलाइन्स पम्प के सामने, हल्द्वानी, नैनीताल) के द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर चोर गलिया क्षेत्र (अपर नन्धौर नदी) में उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के प्राविधानानुसार उपखनिजों के चुगान की अनुमति हेतु किये गये आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2021 एवं प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 15.06.2021 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1873/VII-A-1/2021-05(28)/2021, दिनांक 10 नम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के प्राविधानानुसार एन0एच-87 के निर्माण कार्य के लिए उपखनिज की आपूर्ति हेतु ए0पी0एस0 इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा0लि0, डी-138, सेक्टर-51, नोयडा, उत्तराखण्ड (वर्तमान पता-मोटा हल्दू रिलाइन्स पम्प के सामने, हल्द्वानी, नैनीताल) के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर चोर गलिया क्षेत्र (अपर नन्धौर नदी) में उपखनिज (आर0बी0एम0) की निकासी हेतु शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति की अनुमति जिलाधिकारी, नैनीताल को प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिये जाने हेतु आख्या सादर से निर्णयार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (एस0एल0 पैट्रिक)
 निदेशक

31-03-22
310 बि०

36

द्वारा ई-मेल

व० 31 सेवा में,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
जनपद-नैनीताल

1. उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।
3. सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक: J528 / भूखनि0इ0/सि0ड्रेजिंग/2021-22

दिनांक-26 मार्च 2022

विषय: उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति-2021 के बिन्दु संख्या: 10(2) के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत ठेकेदारों को रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं० 1918/30 जी०सी०/2021-22 दिनांक 25 मार्च, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खण्ड अनुभाग-1 के पत्र सं० 2370/VII-A-1/2022/5(120)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जनपद नैनीताल तहसील हल्द्वानी के अपर नद्यौर चोरगलिया क्षेत्र (अपर नद्यौर नदी) में जमा मलवा/आर०बी०एम० की निकासी एन०एच०-87 के निर्माण कार्य हेतु ए०पी०एस० इन्फ्राटेक इन्जीनियर्स प्रा० लि० के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत अनुज्ञा आदेश की छायाप्रति प्रेषित करते हुए प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में प्ररनगत स्थल के संयुक्त सीमांकन हेतु दिनांक 28.03.2022 को प्रातः 11:30 बजे की तिथि निर्धारित की जाती है। उक्त दिनांक को निर्धारित तिथि को मोकें पर आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि उक्त स्थल पर उपस्थित रहने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें, ताकि उपरोक्त क्षेत्र का संयुक्त सीमांकन कर कृत कार्यवाही से सक्षम स्तर को अवगत कराते हुए प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

12-1
6197
26/03/2022

26/3/22
(राजपाल तेषा)
अपर निदेशक

पृष्ठांक: /तददिनांकित।
प्रतिलिपि :-

जिलाधिकारी, नैनीताल को उनके उपरोक्त पत्रांक के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अपर निदेशक)



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05948-220002, ईमेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक- 1951 /12-1 हल्द्वानी दिनांक- 28 /03 /2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय:-

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत ठेकेदारों को रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुकूल के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका कार्यालय पत्रांक -1918/30-जी.सी./2021-22 दिनांक-25.03.2022।

महोदय,

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2370/VII- A-1/2022/ 5 (120) /21 दिनांक-07 जनवरी, 2022 के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 72 में निहित प्रावधान का समस्त अधिनियमों, विधियों आदि पर अध्यारोही प्रभाव होने के फलस्वरूप शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबन्ध अन्य किसी विधि या अधिनियम से असंगत होते हुए भी प्रभावी होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 10(2) के प्रावधानानुसार ड्रेजिंग कार्य हेतु नदी के समुचित चैनलाईजेशन, नदी के बहाव को सुव्यवस्थित करने तथा आस-पास के गांव/क्षेत्रों में बाढ़ व जनहानि से बचाव आदि के दृष्टिगत जनपद नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के अपर नन्धौर चोरगलिया क्षेत्र (अपर नन्धौर नदी) में जमा मलवा/आर.बी.एम. की निकासी एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. के पक्ष में 08 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने तथा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु संख्या-11 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-68 के अन्तर्गत नियम 54 को शिथिल करते हुए इस कार्य हेतु जमा आर.बी.एम. की मात्रा पर देय रॉयल्टी की धनराशि व अन्य देय धनराशि को 06 समान किशतों में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

यह भी अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली अनुज्ञा के क्रम में ए. पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. द्वारा निकासी किये जाने वाले मलवा आर.बी.एम. की आपूर्ति एन.एच. निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्रेशर को करते हुए तैयार माल का उपयोग संबंधित इकाई द्वारा एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु किया जायेगा। ए.पी.एस. इन्फ्रा इन्जीनियर्स प्रा.लि. के पक्ष में एन.एच. 87 के निर्माण कार्य हेतु दी जा रही अनुज्ञा अनुमति मात्र एन.एच. परियोजना कार्य हेतु प्रदत्त की जा रही है, संबंधित कार्यदायी इकाई द्वारा किसी भी दशा में इसका व्यावस्थायिक उपयोग नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, नैनीताल का पत्र दिनांक 28 मार्च 2022 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत स्थल के संयुक्त सीमांकन हेतु दिनांक 28 मार्च 2022 को समय प्रातः 11:30 बजे की तिथि निर्धारित की गई है।

इस सम्बन्ध में आपको अधगत कराना है कि—

1. नन्धौर नदी के अपर नन्धौर का क्षेत्र नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य के इको-सेन्सेटिव जोन का भाग है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 मई 2020 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में पाये जाने वाले जीव-जन्तु बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधता की दृष्टि से सुरक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उक्त गजट नोटिफिकेशन की धारा 4 में वाणिज्यिक खनन, पत्थर, उत्खनन और अपघर्षण इकाईयों के क्रियाकलाप को निषेध किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त गजट नोटिफिकेशन के प्राविधानों की प्रभावी निगरानी के लिए अधिनियम की धारा 5 में एक निगरानी समिति के गठन का प्राविधान है जिसके पदेन अध्यक्ष कलेक्टर/जिलाधिकारी, नैनीताल हैं।
2. जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, चम्पावत की नदियाँ यथा गौला, कोसी, नन्धौर, शारदा आदि नदियों में उप खनिज के चुगान की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है एवं अनुमति से पूर्व भारतीय जल एवं मृदा संरक्षण संस्थान की सर्वे रिपोर्ट, पर्यावरण प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की सी0ए0ए0, सी0टी0ओ0 रिपोर्ट, पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 आदि की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ताकि उप खनिज चुगान से पर्यावरण एवं वन्य जीवों के वासस्थल में कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। प्रश्नगत स्थल आरक्षित वन है तथा नन्धौर वन्यजीव अभ्यारण्य के इको-सेन्सेटिव जोन के अन्तर्गत आता है।
3. यह भी अवगत कराना है कि इसी प्रकार से एक आदेश केरल राज्य द्वारा पम्बा नदी में Sand Desilting के सम्बन्ध में जारी किया गया था। जिसमें मा० न्यायालय N.G.T (Southern Zone) द्वारा स्वतः संज्ञान (Suo-Motu) से लिया गया एवं O.A.NO 01/2021 Tribunal on its own motion Suo Motu बनाम भारत सरकार व अन्य योजित हुआ, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया एवं वाद विचारित हुआ, उक्त वाद में गठित तकनीकी समिति द्वारा MoEF & CC द्वारा जारी EIA Notification 2006 यथा संशोधित 2016 के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य बताया गया है।
4. इसी प्रकार के समान प्रकरण में मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 1627-1628/2022 (Diary No. 19961/2020) विनय कुमार दलाई व अन्य बनाम ओडिसा राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2022 को आदेश पारित किया गया है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है, इसका भी अवलोकन कर लिया जाय।

अतः उक्त कार्य को करने से कोई विधिक समस्या उत्पन्न न हो इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निम्न प्रकार अनुरोध है—

- i. प्रश्नगत क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र एवं नन्धौर वन्यजीव अभ्यारण्य का इको-सेन्सेटिव जोन है। इको-सेन्सेटिव जोन की निगरानी समिति है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी नैनीताल है। समिति में जिलाधिकारी चम्पावत, पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि, शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, पारिस्थितिकीय और पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी सदस्य हैं। अतः समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय।
- ii. प्रश्नगत क्षेत्र आबादी से दूर है।
- iii. निकासी की जाने R.B.M की मात्रा का निर्धारण भारतीय जल एवं मृदा संरक्षण संस्थान/IIIT Roorkee से स्थलीय निरीक्षण कराकर उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सुनिश्चित की जाय।

- iv. क्योंकि प्रश्नगत स्थल नन्धौर वन्यजीव अभ्यारण्य के इकोसॅसटिव एवं शिवालिक ऐलिफेण्ट रिजर्व का भाग है अतः नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से भी रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय।
- v. पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन दृष्टिगत MoEF & CC द्वारा जारी EIA Notification 2006 यथा संशोधित 2016 के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्थानों से भी रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक / उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

6/11

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.**- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Collector, Nainital	Chairman, ex officio
(ii)	Representative of Collector of Champawat	Member;
(iii)	Representative of the Department of Environment, Government of Uttarakhand	Member;
(iv)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Uttarakhand	Member;
(v)	Regional officer, Uttarakhand State Pollution Control Board	Member;
(vi)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	One expert in the area of ecology & environment to be nominated by the State Government for a term of one year in each case	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Haldwani Forest Division	Member-Secretary.

6. **Terms of reference.** - (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS
27.04.2022		<p>WPPIL No. 48 of 2022 <u>Sri S.K. Mishra, A.C.J.</u> <u>Sri R.C. Khulbe, J.</u></p> <p>Mr. Sandeep Tiwari, learned counsel for the petitioner.</p> <p>Mr. Lalit Sharma, learned Standing Counsel for the Union of India.</p> <p>Mr. S.S. Chauhan, learned Deputy Advocate General for the State.</p> <p>Issue notice to respondent No.7, returnable in four weeks.</p> <p>Postal requisite be filed within one week.</p> <p>Keeping in view the observations made by the National Green Tribunal, Southern Zone, Chennai in O.A. No.75 of 2020 (SZ) on 19.04.2022, in the matter of <i>Tribunal on its own motion vs. Chief Secretary of Kerala</i>, appearing at Page No.70 of the order, <i>vide Clause (v)</i>, we, hereby, permit dredging of river Nandhaur, but we prohibit the removal of any riverbed material (RBM) from the river for any purpose, whatsoever. The same may be kept on the banks of the river, or in the nearby forest.</p> <p>List this case along with Writ Petition (PIL) No.47 of 2022.</p>

In the meantime, counter-affidavits may be filed by the respondents.

Stay Application (IA No.01 of 2022) stands disposed of.

(R.C. Khulbe, J.)
27.04.2022

(S.K. Mishra, A.C.J.)
27.04.2022

NISHANT



No. J-11015/362/2009-IA.II (M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Impact Assessment Division

Indira Paryavaran Bhavan,
Prithvi Wing, 3rd Floor, Aliganj,
JorBagh Road, New Delhi-110 003

Dated: 1st March, 2021

To,

M/s Uttaranchal Forest Development Corporation
AranyaVikasBhawan,
73, Nehru Road,
Dehradun-248 001
E-mail: uafdemd@yahoo.com, Vanvikas12@gmail.com

Subject.: Collection of Reta, Bajri and Boulder (Minor Mineral) from the River Bed of Sharda River by M/s Uttaranchal Forest Development Corporation, located in Tanakpur in the Haldwani Forest Division, District Champawat, Uttarakhand-Extension of validity of EC regarding.

Ref.:- Proposal No. IA/UK/MIN/8720/2011.

Sir,

This is with reference to proposal no. IA/UK/MIN/8720/2011 of M/s Uttaranchal Forest Development Corporation for Amendment w.r.t. the extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 11th February, 2023. The EC was granted vide Letter No. J-11015/362/2009-IA.II(M) dated 15.04.2011 for Collection of Reta, Bajri and Boulder (Minor Mineral) from the River Bed of Sharda River, located in Tanakpur in the Haldwani Forest Division, District Champawat, Uttarakhand (384.69 ha).

2. As per EIA Notification dated 14th September, 2006 as amended from time to time, the project falls under Category B or Activity 1(a) as the mining lease area is more than 100 ha.

2. PP has submitted that Environmental Clearance was granted vide Letter No. J-11015/362/2009-IA.II(M) dated 15.04.2011 wherein at Para 6 of EC letter it has specifically mentions that, "The Ministry of Environment and Forests has examined the application in accordance with the EIA Notification, 2006 and hereby accords environmental clearance for

M/s Uttaranchal Forest Development Corporation

Page 1 of 3

Paulraj Kumar

[Handwritten mark]

a period of 10 years or till the forestry clearance whichever is earlier, *subject to implementation of the following conditions and environmental safeguards.*" PP submitted that MoEF&CC vide its letter F. No. 8-61/1999-FC (pt-III) dated 11.02.2013 granted Forest Clearance for a period of 10 years and is valid till 11.02.2023. Since, EC is also valid for a period of 10 years i.e. till 14.04.2021, therefore, PP has requested for extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 11th February, 2023 for hassle free operations and applied for extension of validity of EC vide its Proposal No. IA/UK/MIN/8720/2011 dated 30.07.2020 and the proposal is placed in EAC meeting held during 19-21 August, 2020.

3. Based on the document submitted and discussion held the Committee recommended the proposal of extension of validity of EC dated 15.04.2011 till 11.02.2023.

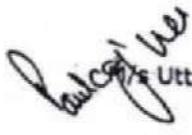
4. The Ministry of Environment, Forest & Climate Change has examined the proposal in accordance with the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and further amendments thereto; and after accepting the recommendation of EAC meeting held during 19-21 August, 2020 hereby decided to accord the amendment of Environmental Clearance under the provisions there to the above mentioned proposal for grant of extension of validity of EC coterminous with the validity of Forest Clearance i.e. 11.02.2023 of M/s Uttarakhand Forest Development Corporation for mine lease area of 384.69ha by M/s Uttarakhand Forest Development Corporation. All other terms & conditions of the Environmental Clearance granted vide J-11015/363/2009-IA-II(M) dated 13.04.2011 shall remain same and Environmental Clearance is valid up to 11.02.2023.

5. The PP shall implement the conditions prescribed in Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, as applicable for PP. Implementation report with supporting documents & photographs before and after shall be submitted to the Regional Office of MoEF&CC before 1st July of every year for the activities carried out during previous year.

6. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

7. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

8. The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Court and any other Court of law relating to the subject matter.


Uttarakhand Forest Development Corporation

9. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

10. These issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

Pankaj Verma

(Pankaj Verma)

Scientist 'E'

Email- pankaj.verma@nic.in

Tel./Fax- 011- 24695264

Copy to:

- 1). The Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
- 2). The Secretary, Department of Mines & Geology, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
- 3). The Secretary, Department of Environment, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
- 4). Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
- 5). The Chief Conservator of Forests, Central Region, Ministry of Environment and Forests, B-1/72, Sector A, Aliganj, Lucknow-226020.
- 6). The Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan, CBD-cum-Office complex, East Arjun Nagar, New Delhi-1100032.
- 7). The Member Secretary, Central Ground Water Authority, A-2, W3, Curzon Road Barracks, K.G. Marg, New Delhi-110001.
- 8). The Member Secretary, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, E-115, Nehru Colony, Hardwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
- 9). The Controller General, Indian Bureau of Mines, Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440 001.
- 10). The District Collector, Haldwani District, Uttarakhand.
- 11). Guard File.
- 12). PARIVESH PORTAL.

Pankaj Verma

(Pankaj Verma)

Scientist 'E'

Email- pankaj.verma@nic.in

Tel./Fax- 011- 24695264

E.C

No. J-11015/362/2009-IA.II(M)

Government of India

Ministry of Environment and Forests

IA Division

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003

Dated the 15th April, 2011

To

M/s Uttaranchal Forest Development Corporation
Aranya Vikas Bhawan,
73, Nehru Road,
Dehradun-248 001
E-mail: uafdemd@yahoo.com
Vanvikas12@gmail.com

श्री
स्वीयन ३०/४/२०११

Subject: Collection of Reta, Bajri and Boulder (Minor Mineral) from the River Bed of Sharda River by M/s Uttaranchal Forest Development Corporation, located in Tanakpur in the Haldwani Forest Division, District Champawat, Uttarakhand -environmental clearance regarding.

Sir,

This has reference to your letter No. U-2986/Environmental clearance dated 09.09.2010 and subsequent letters dated 15.11.2010, 11.01.2011 and 14.01.2011 on the subject mentioned above. The project was earlier prescribed Terms of Reference (TORs) by the Ministry of Environment and Forests on 15.02.2010 for undertaking detailed EIA study for the purpose of obtaining environmental clearance. The proposal is for extraction of 21.6 lakh tonnes per annum (LTPA) of reta, bajri and boulder (minor mineral) from the river bed of Sharda River, District Champawat, Uttarakhand.

2. The total mine lease area of the project is 384.69ha, which is a forestland falling under the Haldwani Forest Division in Champawat District. It was stated by the proponent that although the lease has been granted to them in perpetuity, however, since the forestry clearance is for a period of 10 years, the environmental clearance may also be granted for a maximum period of 10 years to make it co-terminus with the forestry clearance. The total length of the Sharda River under the Haldwani Forest Division being proposed under the project is approximately 12km. Out of the total allotted area of 384.69ha, the minor mineral collection will be carried out from 50% of the total area i.e. 192.35ha leaving 25% area on each side of the river banks. The area available for mining would therefore be 192.35ha along the centre of the river flow, which is devoid of any flora.

3. No national park and wildlife sanctuary are reported to be located in the core and buffer zone of the mine. The project area falls under the Shivalli Elephant Reserve. The Jim Corbett National Park is reported to be located at a distance of 2 km from the project area.

...2/

distance of 110km NW from the project boundary. The Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand vide letter No.1192/12-1 dated 08.12.2010 has accorded NOC for collection of minor mineral from the Sharda River in an area of 384ha. An authenticated map has also been submitted. It was stated that the forest working plan, being implemented by State Forest Department include protection of wildlife and this would be duly taken care of while picking up of reta, bajri and sand. The Kakrali RF, the Daun RF, the Naghar RF, the Bastia West RF and the Bastia East RF are reported to be located in the buffer zone of the mine. These forests are miscellaneous type and witness dense growth of Sal- Sagwan followed by other trees.

4. The mine working will be opencast by manual method without involving drilling and blasting. The mining is confined to extraction of sand, reta and bajri from the river bed. The reta and bajri will be collected by sieving of river bed material using hand tools like shovel, pan, sieve etc. Mining will be carried out only during the day time. Extraction of river bed material will be completely stopped during the monsoon season. The targetted production capacity of the mine is 21.6Lakh TPA (12Lakh m³ per annum) of river bed material. The river bed material will be replenished during the monsoon season every year. The mined out material will be transported to their respective uses locations via private agencies using their own transport. Computerized weigh bridges have been installed in order to check and monitor moment of material. The proposed mining area is reported to lie between 29°05'56.03" to 29°04'45.49" N Latitude and 80°08'12.47" to 80°07'10.85" E Longitude in topo sheet No. 62 C/4. The elevation from the sea level of the proposed area is reported as 510.61m. Mining will be carried out upto a depth of 1.5m. The quantity of mineral to be removed has been fixed based on replenishment rate.

5. The public hearing of the project was held on 23.08.2010 for lease area of 384.69ha for collection of river bed material from the Sharda River. The Principal Secretary, Government of Uttarakhand vide letter No.2536/VII-I/163-KHA/2009/10 dated 23.10.2010 informed that collection of minor mineral from the river bed does not require mine plan approval under Uttarakhand Minor Mineral Concession Rules 2001. The Ministry of Environment and Forests has accorded Stage-I approval under Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 384.69ha forestland on 08.04.2011 for collection of stone, boulders and other minor minerals from the river bed of Sharda River in the District Champawat. The proponent has stated that there is no court case to the project or related activity.

6. The Ministry of Environment and Forests has examined the application in accordance with the EIA Notification, 2006 and hereby accords environmental clearance under the provisions thereof to the above mentioned Minor Mineral (reta, bajri and boulder) Mining Project of M/s Uttaranchal Forest Development Corporation for an annual collection of 21.6Lakh Tonnes of reta, bajri and boulder (minor mineral) from the Sharda River bed by the opencast method involving total mining lease area of 384.69ha, for a period of 10 years or till the forestry clearance whichever is earlier, subject to implementation of the following conditions and environmental safeguards.

A. Specific conditions

- (i) The project proponent shall obtain Consent to Establish and Consent to Operate from the Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board and effectively implement all the conditions stipulated therein.
- (ii) The environmental clearance is subject to grant of forestry clearance. The project proponent shall obtain requisite prior forestry clearance under the Forest (Conservation) Act, 1980 for working in the forest area.
- (iii) The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
- (iv) Requisite prior clearance from the Standing Committee of the National Board for Wildlife shall be obtained due to location of the project area within Shivalik Elephant Reserve, before starting any activity relating to the project at site. All the conditions stipulated by the Standing Committee shall be effectively implemented in the project. It shall be noted that this clearance does not necessarily implies that wildlife clearance shall be granted to the project and that your proposal for wildlife clearance shall be considered by the competent authorities on its merit and decision taken. The investment made in the project, if any based on environmental clearance granted to the project, in anticipation of the clearance from wildlife clearance shall be entirely at the cost and risk of the project proponent and Ministry of Environment and Forests shall not be responsible in this regard in any manner.
- (v) Environmental clearance is subject to final order of the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 460 of 2004, as may be applicable to this project.
- (vi) Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent authority, as may be applicable to this project.
- (vii) The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked, distance from the bridges etc. It shall be ensured that no mining shall be carried out during the monsoon season.
- (viii) The project proponent shall identify the degraded forest area within the mine lease in consultation with the State Forest Department and undertake plantation/afforestation work by planting the native species.

- (ix) Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high level of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
- (x) The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out around the mine lease area by establishing a network of existing wells and installing new piezometers during the mining operation. The periodic monitoring [(at least four times in a year pre-monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January); once in each season)] shall be carried out in consultation with the State Ground Water Board/Central Ground Water Authority and the data thus collected may be sent regularly to the Ministry of Environment and Forests and its Regional Office Lucknow, the Central Ground Water Authority and the Regional Director, Central Ground Water Board. If at any stage, it is observed that the groundwater table is getting depleted due to the mining activity, necessary corrective measures shall be carried out.
- (xi) The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of water (surface water and groundwater), if any, required for the project.
- (xii) Appropriate mitigative measures shall be taken to prevent pollution of the river in consultation with the State Pollution Control Board. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles used for transportation.
- (xiii) Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The mineral transportation shall be carried out through the covered trucks only and the vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
- (xiv) No drilling and blasting operation shall be carried out.
- (xv) Mineral handling area shall be provided with the adequate number of high efficiency dust extraction system. Loading and unloading areas including all the transfer points should also have efficient dust control arrangements. These should be properly maintained and operated.
- (xvi) Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.

- (xvii) Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- (xviii) Digital processing of the entire lease area using remote sensing technique should be done regularly once in three years for monitoring the change of river course, if any and report submitted to the Ministry of Environment and Forests and its Regional Office located at Lucknow.
- (xix) The project proponent shall take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered fauna namely elephant etc. found in the study area. Action plan for conservation of flora and fauna shall be prepared in consultation with the State Forest and Wildlife Department. All the safeguard measures brought out in the Wildlife Conservation Plan so prepared specific to this project site shall be effectively implemented. Necessary allocation of funds for implementation of the conservation plan shall be made and the funds so allocated shall be included in the project cost. A copy of action plan shall be submitted to the Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Lucknow.
- (xx) The critical parameters such as RSPM (Particulate matter with size less than 10micron i.e., PM_{10}) and NO_x in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water shall also be monitored [(TDS, DO, PH, Fecal Coliform and Total Suspended Solids (TSS)]. The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed on a display board at the project site at a suitable location near the main gate of the Company in public domain. The Circular No. J-20012/1/2006-IA.II(M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment and Forests, which is available on the website of the Ministry www.envfor.nic.in shall also be referred in this regard for its compliance.
- (xxi) The project proponent shall get a siltation study carried out within one year through some Expert Agency like Central Water Commission to determine the siltation load in the river bed so that there is no over-exploitation of river bed material at any point of time. The mineral to be removed shall be determined based on siltation load. A copy of siltation study so carried out shall be submitted to the Ministry of Environment and Forests and its Regional Office Lucknow.

B. General conditions

- (i) No change in mining technology and scope of working should be made without prior approval of the Ministry of Environment & Forests.
- (ii) No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral, rets, bajri and boulders (minor mineral) and waste should be made.

- (iii) Four ambient air quality monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for RSPM (Particulate matter with size less than 10micron i.e., PM₁₀) and NO_x monitoring. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board.
- (iv) Data on ambient air quality RSPM (Particulate matter with size less than 10micron i.e., PM₁₀) & NO_x should be regularly submitted to the Ministry of Environment and Forests including its Regional office located at Lucknow and the State Pollution Control Board / Central Pollution Control Board once in six months.
- (v) Fugitive dust emissions from all the sources should be controlled regularly. Water spraying arrangement on haul roads, loading and unloading and at transfer points should be provided and properly maintained.
- (vi) Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
- Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
- (vii) A separate environmental management cell with suitable qualified personnel should be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
- (viii) The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year wise expenditure should be reported to the Ministry of Environment and Forests and its Regional Office located at Lucknow.
- (ix) The project authorities should inform to the Regional Office located at Lucknow regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
- (x) The Regional Office of this Ministry located at Lucknow shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- (xi) The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions

- (xii) including results of monitored data (both in hard copies as well as by e-mail) to the Ministry of Environment and Forests, its Regional Office Lucknow, the respective Zonal Office of Central Pollution Control Board the State Pollution Control Board. The proponent shall upload the status of compliance of the environmental clearance conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Lucknow, the respective Zonal Office of Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board.
- (xiii) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
- (xiv) The State Pollution Control Board should display a copy of the clearance letter at the Regional office, District Industry Centre and the Collector's office/ Tehsildar's Office for 30 days.
- (xv) The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Lucknow by e-mail.
- (xvi) The project authorities should advertise at least in two local newspapers of the District or State in which the project is located and widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the Ministry of Environment and Forests at <http://envfor.nic.in> and a copy of the same should be forwarded to the Regional Office of this Ministry located at Lucknow.

7. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

8. Failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

2.8/-

2.8/-

9. The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made thereunder and also any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Court of Uttarakhand and any other Court of Law relating to the subject matter.

(SATISH.C.GARKOTI)
Scientist 'F'

Copy to:

- (i) The Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
- (ii) The Secretary, Department of Mines & Geology, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
- (iii) The Secretary, Department of Environment, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
- (iv) Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
- (v) The Chief Conservator of Forests, Central Region, Ministry of Environment and Forests, B-1/72, Sector-A, Aliganj, Lucknow-226020.
- (vi) The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan, CBD-cum-Office complex, East Arjun Nagar, New Delhi-1100032.
- (vii) The Member Secretary, Central Ground Water Authority, A-2, V.B. Curzon Road Barracks, K.G. Marg, New Delhi-110001.
- (viii) The Chairman, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, E-115, Nehru Colony, Hardwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
- (ix) The Controller General, Indian Bureau of Mines, Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440 001.
- (x) The District Collector, Champawat District, Uttarakhand.
- (xi) E1 Division, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, C. G. O Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003.
- (xii) Monitoring File.
- (xiii) Guard File.
- (xiv) Record File.

(SATISH.C.GARKOTI)
Scientist 'F'

P. No. 8-61/ 1999 - FC. (pt-III)
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

198/x-3-13-8 (14) 9 T.C.L

Paryavaran Bhawan,
CCO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110 003
Dated 11th February, 2013

To,

The Principal Secretary (Forests)
Forest and Revenue Department,
Government of Uttarakhand,
Dehradun

Sub: Proposal to obtain prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980, for collection of stone, boulders and other minor minerals from 384.69 hectares of forest land located in river bed of Sharda river in Champawat district of Uttarakhand by the Uttarakhand Forest Development Corporation Ltd.

Sir,

I am directed to refer to the Addl. Principal Chief Conservator of Forests & the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Uttarakhand's letter No. 538/ IC-2755 (Champo.) dated 22.08.2009 and No. 879/ 1G - 2755 (Champo.) dated 09.10.2012 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the said proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the aforesaid Act. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the said Act, in-principle approval for the said diversion was granted vide this Ministry's letter of even number dated 10.01.2013 subject to fulfilment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

2. In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the Addl. Principal Chief Conservator of Forests & the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Uttarakhand vide letters No. 1691/1G-2755 (Champo.) dated 23.01.2013 and No. 1828/1G - 2755 (Nani) dated 07.02.2013, approval of the Central Government is hereby granted under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for collection of stone, boulders and other minor minerals from 384.69 ha. forest land located in river bed of Sharda river in Champawat district of Uttarakhand by the Uttarakhand Forest Development Corporation Ltd. for a period of ten years by the Uttarakhand Forest Development Corporation, subject to fulfilment of the following conditions:

- (1) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

- (i) Compensatory afforestation over the degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency;
- (ii) All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Saving Bank Account of the concerned State CAMPA in the Corporation Bank, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi;
- (iii) No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Sharda river located on upstream of the Sharda barrage;
- (iv) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the forest land proposed for diversion;
- (v) The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand constituted vide Government of Uttarakhand's letter No. 14-1/X-3-13-08(14)/2008-T.C. dated 29.01.2013 to the effect that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year;
- (vi) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with proposed Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sunderkhal village by using State CAMPA funds;
- (vii) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited in a Special Purpose Vehicle (SPV) constituted by the State Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand vide order No. 383/X-3-12-8(14)/2009 dated 30th May 2012. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals;
- (ix) The State Government shall through the Central Soil and Water Conservation Research & Training Institute (CSWCRTI), Dehradun assess the quantity of the minor minerals that may sustainably be collected from the said portion of the Sharda river and intimate the same to the Ministry of Environment & Forests;
- (x) The quantity of minor mineral collected during a working season shall not be more than the sustainable quantity as assessed by the CSWCRTI, Dehradun;
- (xi) Extraction of minor minerals shall be restricted to middle half of the width of river bed after leaving intact the one-fourth of width of the river bed along its each bank.
- (xii) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary

of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 m and it shall gradually reduce till it reaches boundary of the permissible zone;

- (xiii) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season;
- (xiv) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year;
- (xv) Minor minerals shall be collected by manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited;
- (xvi) Collection time shall be from sun-rise to sun-set;
- (xvii) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals;
- (xviii) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries;
- (xix) The labourers engaged in collection work will be provided free fuelwood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land;
- (xx) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoin pillars etc.;
- (xxi) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;
- (xxii) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry;
- (xxiii) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and
- (xxiv) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

Yours faithfully

(H. C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand, Dehradun.

• Nodal Officer, Forest Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

• Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office (Central Zone),
Dehradun.

• State Agency.

• Monitoring Cell, Ministry of Environment and Forests.

• Record File.

(H. C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

[Handwritten mark]



HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)

Web : www.ukpcb.org In. E-mail : ukpcb@ukpcb.org
Ph. No. 2976157, 2976158, 2687892

UKPCB/HO/Con/P-155/2022/481

Date : 07.01.2022
REGD. POST

To,

M/s Prabhagiya Van Vikas Prabhanda,
(Khanan Sharda),
Uttarakhand Van Vikas Nigam,
Rambagh Road, Purnagiri,
Tanakpur, Distt. Champawat.

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

CAF ID - 7749
CCA (Renewal)

Application No. - 1508793
Date :- 09.08.2021

CCA is hereby granted to M/s Prabhagiya Van Vikas Prabhanda (Khanan Sharda River Bed-Total allotted area-384.69 Hect.) of Uttarakhand Van Vikas Nigam, Rambagh Road, Purnagiri, Tanakpur, Distt. Champawat subject to the provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is granted for the period upto 11.02.2023 and valid for mining of following activities with Capital Investment/Net Assets Values ₹ 5.29 Lacs. :-

S. No.	Last CCA		Present CCA (Renewal)	
	Activity	Quantity (Per Year)	Activity	Quantity (Per Year)
1	Mining of Minor Minerals-Reta, Bajri and Boulders	21,60,000 MT	Mining of Minor Minerals-Reta, Bajri and Boulders	21,60,000 MT

2. Specific Conditions under Water Act :-

- (i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

	Last CCA	Present CCA (Renewal)
Trade Effluent	Nil	Nil
Sewage	0.8	2.0

- (ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :- Nil.....

- (iii) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive Septic Tank/Soak pits as is required with reference to influent quantity and quality.

3. Conditions under Air Act :-

- (i) The applicant shall not use any fuel.
(ii) Unit has to maintain ambient air quality and ensure that the same be kept within norms as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986.

[Handwritten signature]

UKPCB

(iii) Unit has to follow ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. **Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 :-** There shall not be any hazardous waste, hence this rule is not applicable.
5. This CCA is valid for extraction of river bed material by manual method only.
6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**
 - (i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.
8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

all Member Secretary

Copy to: Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital for information and compliance of the same.

S. M. 4.12.2
Chief Environment Officer

all *JTB*

all

UKPCB

Annexure

Specific Conditions:

1. The Occupier shall under take mining in conformity with approved Mining Plan with the conditions and Rules prescribed in this regard, and instruction issued time to time.
2. The Occupier shall make permanent pillar(s) along the boundary of the mining area and shall display details as- Name of Occupier, Lease Date & Validity, Lease Area etc. at prominent place.
3. The Occupier shall ensure that whatever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
4. The Occupier shall ensure regular water sprinkling in an area critically prone to air pollution and having high levels of Particulate Matter (PM) such as loading and unloading points and all transfer points.
5. The Occupier shall undertaken adequate safeguard measures during extraction of minor minerals and ensure that due to this activity the hydro-geological refine of surrounding area shall not be affected.
6. Vehicular emission shall be kept under Control and regularly monitored. The sand, bajri & boulders shall be carried out through the covered trucks only and vehicles carrying the sand/bajri/boulders shall not be overloaded.
7. Project Proponent shall ensure that the road may not be damaged due to transportation of the mineral and transport of minerals will be as per IRC Guidelines with respect to complying with traffic congestion and density.
8. Periodical medical examination of workers engaged in mining activity shall be carried out and records maintained.
9. The Occupier shall take all precautionary measures during mining operation for conservation & protection of endangered fauna & flora etc.
10. No change shall be made in mining technology and scope of mining work without prior approval of competent authority.
11. Mining shall be carried out in stipulated time and duration as permitted by competent authority.
12. The Occupier shall comply with the directions/instructions issued by the competent authority from time to time.
13. The Occupier shall strictly adhere to the conditions of Environment Clearance issued by the competent authority & provisions of approved mining plan, scrupulously.
14. The occupier shall comply with the Environment Management Plan and shall execute proposed environment management activities, scrupulously.
15. A Final Mine Closure Plan along with details of Corpus Fund shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change 5 years in advance of final mine closure for approval.
16. The Occupier(s) shall mark the mining area as per allotted mining lease by Competent Authority and mining shall be carried out only in approval mining area.
17. The Occupier shall ensure to submit Ambient Air Quality Report at quarterly basis.
18. The Project Proponent shall undertake phased restoration, reclamation and rehabilitation of land affected by mining and completes this work before abandonment of mine.
19. Air Pollution due to dust, exhaust emission or fumes during mining and processing phase should be controlled and kept in permissible limits specified under environmental laws.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF&CC and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.

UKPCB

4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
11. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without permission of Board.

[Signature]
Chief Environment Officer

EU
[Signature]

[Signature]

:: आदेश ::

62

(अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005)

जनपद चम्पावत की तहसील श्री पूर्णागिरी (टनकपुर) अन्तर्गत विगत वर्षों में मानसून अवधि के दौरान शारदा नदी के किनारे बसे गाँव यथा- उचौलीगोट, गैड़ाखाली 1, 3 व 4, सुवागोट, बसानीगोट, नायकगोट, थ्यालखेड़ा, खेतखेड़ा तथा शारदा घाट के पास शारदा चुंगी क्षेत्रों में शारदा नदी के जल स्तर बढ़ने से भू-कटाव एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके दृष्टिगत प्रभावित स्थान के प्रभावितों द्वारा समय-समय पर शारदा नदी में उक्त स्थान पर बाढ़ से संबंधित सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड के जनपद चम्पावत भ्रमण के दौरान भी तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) अन्तर्गत शारदा नदी से लगे हुये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। भ्रमण के दौरान आमजनता द्वारा भी मा. मुख्यमंत्री जी को मानसून अवधि के दौरान शारदा नदी के जलस्तर बढ़ जाने के कारण होने वाली क्षति तथा शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन से दूरभाष पर वार्ता कर उक्त समस्या के निराकरण हेतु निर्देश दिये गये। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन से हुयी वार्ता के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र संख्या- 37344/स्टाफ आफि.-मुख्य सचिव/प्र.नि.स./2022 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 द्वारा दिनांक 05.04.2022 को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तात्कालिक बैठक आहूत की गयी।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि तात्कालिकता के दृष्टिगत आगामी मानसून से पूर्व उक्त स्थान का निरीक्षण करते हुये आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत न्यूनीकरण तथा अन्य बचाव के प्रभावी उपाय कर लिये जायें। जिसके क्रम में आगामी मानसून के दृष्टिगत पूर्व की स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु स्थलीय निरीक्षण व तकनीकी ऑकलन कर तथा उक्त स्थान पर सुरक्षात्मक उपाय हेतु आदेश संख्या-03/xiii-आ.प्र.प्राधि./DM Act-2005/शारदा नदी/ 2022-23 दिनांक- 05 अप्रैल, 2022 निम्नवत् समिति का गठन किया गया-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, चम्पावत।
3. उप जिलाधिकारी, पूर्णागिरी (टनकपुर)।
4. भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी, चम्पावत।
5. प्रभागीय लौंगिक प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर।

उक्त गठित समिति द्वारा मानसून अवधि के दौरान टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायों हेतु दिनांक 06.04.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें उनके द्वारा आगामी मानसून-2022 से पूर्व शारदा नदी पर निम्नवत् सुरक्षात्मक कार्य प्रस्तावित किये गये-

1. ग्राम सभा उचौलीगोट - ग्राम सभा में पूर्व में शारदा नदी में आने वाली बाढ़ के कारण कृषि भूमि का लगभग 11 हेक्टे. क्षेत्रफल नदी में समा चुका है। इस क्षेत्र में शारदा नदी का रुख दौयी ओर होने के कारण भविष्य में भी भू-कटाव का खतरा बना हुआ है। उचौलीगोट ग्राम सभा में शारदा नदी का 28 एकड़ क्षेत्र राजस्व भूमि एवं शोध भाग शारदा रेंज, हल्द्वानी वन प्रभाग का हिस्सा है। यहाँ भू-कटाव से लगभग 18 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, जिन्हें नदी में जल स्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी तौर पर विस्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गाँवों में लगभग 11 हेक्टेयर कृषि भूमि भी भू-कटाव से या तो प्रभावित है या उसकी जड़ में आने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में भविष्य में गाँव को बाढ़ एवं भू-कटाव से बचाये जाने के लिये नदी का वेनेलाइजेशन एवं तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य जैसे तटबन्ध बनाया जाना आवश्यक होगा। आगामी मानसून सीजन में गाँव को भू-कटाव से रोकने हेतु नदी में लगभग 04 हेक्टे. क्षेत्रफल में एकत्रित बड़े-बड़े बाल्टों को हटाकर किनारे की ओर लगाया जाना उचित होगा ताकि भूकटाव रोका जा सके तथा नदी को वैज्ञानिक विधि से वेनेलाइज कर गाँव से दूर प्रवाहित किया जा सके।
2. गैड़ाखाली नं. 1, 3 व 4- ग्राम सभा में पूर्व के वर्षों में शारदा नदी से आने वाली बाढ़ के कारण भूमि का 16 हेक्टे. क्षेत्रफल नदी में समा चुका है। इस क्षेत्र में शारदा नदी का रुख भारत की ओर होने के कारण भविष्य में

W.S.

भी भू-कटाव का खतरा बना हुआ है। गैड़ाखाली ग्राम सभा में शारदा नदी का क्षेत्र शारदा रेंज, हल्द्वानी वन प्रभाग का हिस्सा है। यहाँ भू-कटाव से लगभग 29 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, जिन्हें नदी में जल स्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी तौर पर विस्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गँवों में लगभग 16 हैक्टेयर कृषि भूमि भी भू-कटाव से या तो प्रभावित है या उसकी जद में आने की सम्भावना है। ग्राम सभा में पूर्व में विकसित की गयी फल पट्टी वर्ष 2021 के अक्टूबर माह में आयी बाढ़ में नदी में समा चुकी है, जिसमें आम, लीची एवं अमरुद के बागों को भारी नुकसान हुआ, जिससे कृषकों को कॉफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अतिरिक्त गँव में कृषि योग्य भूमि का बड़े स्तर पर कटाव हुआ है। गैड़ाखाली में इसके अतिरिक्त एक मन्दिर, आश्रम भी भू-कटाव की जद में है। इस क्षेत्र में भविष्य में गँव को बाढ़ एवं भू-कटाव से बचाये जाने के लिये नदी का चैनेलाइजेशन एवं तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य जैसे- तटबन्ध बनाया जाना आवश्यक होगा।

3. सुवागोठ, बसानीगोठ, खेतखेड़ा- ग्राम सभा में पूर्व के वर्षों में शारदा नदी से आने वाली बाढ़ के कारण भूमि का 09 हैक्टे. क्षेत्रफल नदी में समा चुका है। इस क्षेत्र में शारदा नदी का रुख भारत की ओर होने के कारण भविष्य में भी भू-कटाव का खतरा बना हुआ है। उक्त ग्राम सभाओं में शारदा नदी का कुछ क्षेत्र राजस्व विभाग एवं शेष शारदा रेंज, हल्द्वानी वन प्रभाग का हिस्सा है। यहाँ भू-कटाव से लगभग 13 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, जिन्हें नदी में जल स्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी तौर पर विस्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गँवों में लगभग 09 हैक्टेयर कृषि भूमि भी भू-कटाव से या तो प्रभावित है या उसकी जद में आने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में भविष्य में गँव को बाढ़ एवं भू-कटाव से बचाये जाने के लिये नदी का चैनेलाइजेशन एवं तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य जैसे तटबन्ध बनाया जाना आवश्यक होगा।

4. नगर पालिका टनकपुर- टनकपुर नगर पालिका वार्ड नं. 01 के शारदा घाट, अम्बेडकर नगर, खच्चर पड़ाव हिस्से प्रतिवर्ष बाढ़ की जद में आते हैं। यहाँ लगभग 620 परिवार शारदा नदी के तट पर बसे हैं, जोकि शारदा नदी में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से प्रभावित होते हैं। वर्ष 2021 के अक्टूबर माह में आयी बाढ़ से शारदा घाट, खच्चर पड़ाव एवं अम्बेडकर नगर तीन दिन तक जलमग्न रहा तथा लगभग 3480 व्यक्तियों को विस्थापित कर अस्थायी कैम्पों में रखा गया। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित शारदा घाट में भी भारी नुकसान हुआ। यहाँ हनुमानगढी में पूर्व में निर्मित तटबन्धों से नुकसान को कम किया जा सका। वर्तमान में यदि इस क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में नदी का चैनेलाइजेशन किया जाता है तो भविष्य में इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकता है। साथ ही हनुमानगढी में निर्मित तटबन्धों को आगे की ओर बढ़ा कर मजबूत किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दु भी महत्वपूर्ण हैं-

1. जिला चम्पावत के तहसील श्री पूर्णागिरी (टनकपुर) में शारदा नदी के कारण, वर्षा ऋतु के दौरान शारदा नदी के दावें पार्श्व में बसे गँवों उचौलीगोठ, गैड़ाखाली नं. 1, 3 व 4, सुवागोठ, बसानीगोठ, नायकगोठ, थ्यालखेड़ा, खेतखेड़ा तथा शारदा घाट के पास शारदा चुंगी क्षेत्र में भू-कटाव एवं जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
2. बूम से लेकर उक्त क्षेत्रों से होते हुये शारदा चुंगी (शारदा घाट) तक की दूरी लगभग 07 कि.मी. है, इस क्षेत्र में कई स्थानों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किये जाने हैं।
3. आपदा आने से पूर्व ही उक्त समस्त क्षेत्र को खाली करा दिये जाने के कारण जान-माल की क्षति से बचाव हुआ परन्तु भू-कटाव एवं जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुयी।
4. विगत 02 वर्षों में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शारदा अपस्ट्रीम हाथी कोरीडोर का हिस्सा होने एवं दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियाँ होने के कारण चुगान पर रोक लगायी गयी है।
5. वर्ष 2019 से पूर्व शारदा अपस्ट्रीम क्षेत्र में चुगान भारतीय सीमा की ओर किया गया जबकि नेपाल द्वारा अपने क्षेत्र में खनन नहीं किया गया। जिस कारण शारदा नदी का तल नेपाल सीमा की ओर उथला हो गया एवं भारत की सीमा की ओर गहरा होने से नदी का रुख भारत की ओर हो गया जिस कारण ग्राम पंचायत उचौलीगोठ, गैड़ाखाली, खेतखेड़ा, सुवागोठ एवं टनकपुर के शारदा घाट क्षेत्र में अत्यधिक भू-कटाव हुआ है।
6. शारदा नदी के पूर्व (बायें) ओर नेपाल की सीमा है। जिस कारण से नदी तल पर कोई भी कार्य भारत की सीमा में ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नदी तल का वृहद हिस्सा शारदा रेंज, हल्द्वानी वन प्रभाग का हिस्सा है। जिस कारण नदी तल पर व्यवसायिक चुगान/खनन करने से पूर्व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिषद न मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है।

W

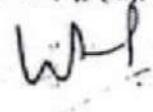
7. शारदा अपस्ट्रीम में वैज्ञानिक विधि से नदी के चैनलाइजेशन की आवश्यकता है। जिसमें कि नदी के मध्य जमा हुये शीवर बैंड मैटेरियल को नदी के पश्चिमी (दाहिने) तट पर जमा किये जाने से तट पर स्थित गाँवों के भू-कटाव को रोका जा सकेगा।
8. उक्त अपस्ट्रीम क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से नदी में पड़ी सामग्री का नदी के किनारों को छोड़कर निरस्तारण किया जाये तो इससे निकटवर्ती ग्रामों में जल भराव/भू-कटाव की स्थिति से निजात मिल सकती है।
उक्त के अतिरिक्त अभिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड लोहाघाट, चम्पावत के पत्र संख्या-C-27/सि.ख.लो./आपदा/2022-23 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि-
- शारदा बैराज की अधिकतम क्षमता 08 लाख क्यूसेक है। वर्ष 2013 में शारदा नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण शारदा बैराज से 5.44 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज प्रवाहित हुआ एवं दिनांक 18-19 अक्टूबर, 2021 में शारदा नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण शारदा बैराज से 5.47 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज प्रवाहित हुआ।
 - शारदा नदी के दाये पार्श्व पर ग्राम बूम, उचौलीगोठ, गैडाखाली नम्बर-01, 03, 04, सुवागोट, थवालखेड़ा, खेतखेड़ा, फायर स्टेशन, घसियारा मंडी स्थित है। उक्त ग्रामों के समीप शारदा नदी में जगह-जगह आर.बी.एम. जमा होने के कारण नदी में डेल्टा बन गये हैं जिसके कारण से नदी का रुख अपनी मुख्य धारा में न बह कर उक्त ग्रामों की ओर मुड़ गया है। जिससे उक्त ग्रामों की कृषि योग्य भूमि का कटाव व जल भराव के साथ-साथ जान माल की क्षति होने की संभावना बनी हुयी है। उक्त ग्रामों की आबादी व जान-माल की क्षति को बचाने हेतु नदी का चैनलाइजेशन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
 - ग्राम गैडाखाली के डाउन स्ट्रीम में स्थित ग्राम सुवागोट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला खनिज न्यास मद के अन्तर्गत 09 मीटर लम्बाई, 06 मी चौड़ाई, 04 मीटर ऊँचाई में 04 स्परों का निर्माण का कार्य किया गया है। शारदा नदी के रुख को अपनी मुख्य धारा में नहीं मिलाये जाने पर अत्यधिक जल स्तर बढ़ने से ग्राम सुवागोट में निर्मित 04 स्पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जिससे जानमाल की हानि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
 - ग्राम उचौलीगोठ के डाउन स्ट्रीम में गैडाखाली के समीप शारदा नदी की चौड़ाई लगभग 1200 मीटर है। मानसून अवधि 2022 से पूर्व नदी के दोनों पार्श्वों से 25 प्रतिशत चौड़ाई को छोड़ते हुए नदी की मुख्य धारा में जमा हुए आर.बी.एम का चैनलाइजेशन किया जायेगा जिसकी लम्बाई 800 मीटर, चौड़ाई लगभग 150 मीटर व गहराई 03 से 04 मीटर है। उक्त ग्रामों की सुरक्षा को देखते हुये शारदा नदी के दाये पार्श्व पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किये जाने अत्यंत आवश्यक है। जिससे कि आगामी मानसून अवधि-2022 से पूर्व उक्त ग्रामों के संभावित खतरे को न्यून किया जा सके।
 - वन विभाग द्वारा उक्त बैठक में अवगत कराया गया कि मानसून अवधि 2022 से पूर्व आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत उक्त कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने हेतु वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु उक्त क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य संपादित करवाये जाने के दौरान यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त क्षेत्र में किसी भी दशा में नदी क्षेत्र से उपखनिजों की निकासी न की जाये।

दिनांक 13.04.2022 को चम्पावत आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी जिसमें सिंचाई विभाग, लोहाघाट चम्पावत द्वारा तर्क दिया गया कि-

- सर्वप्रथम ऐसे स्थल पर चैनलाइजेशन का कार्य किया जाये जहाँ पर चैनलाइजेशन करने से अधिक प्रभावी समाधान निकल सके। उसके प्रभाव को देखने के उपरान्त ही अन्य स्थानों पर चैनलाइजेशन कार्य किया जाना उचित होगा। ऐसा स्थल गैडाखाली न. 1 के समीप गिहिनत किया गया जिनके तर्क पर विचारोंपरान्त तय किया गया कि सर्वप्रथम गैडाखाली न. 1 पर चैनलाइजेशन कार्य मानसून अवधि 2022 से पूर्व कर लिया जाए एवं आगामी वर्षा ऋतु में इसके प्रभाव को आंकलित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाए।
- उपरोक्त के अतिरिक्त बूम से शारदा घाट तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कर लिये जाए।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उपरोक्त बर्णित कार्यों को प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में सिंचाई विभाग लोहाघाट द्वारा सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार में, विनीत तोमर, जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चम्पावत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय-4 की धारा 30 के अन्तर्गत की उपधारा 2(iii), (iv), (v), (xi), (xviii), (xx), धारा 34



7. शारदा अपस्ट्रीम में वैज्ञानिक विधि से नदी के चैनलाइजेशन की आवश्यकता है। जिसमें कि नदी के मध्य जमा भू-कटाव को रोका जा सकेगा।
8. उक्त अपस्ट्रीम क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से नदी में पड़ी सामग्री का नदी के किनारों को छोड़कर निस्तारण किया जाये तो इससे निकटवर्ती ग्रामों में जल भराव/भू-कटाव की स्थिति से निजात मिल सकती है।
उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड लोहाघाट, चम्पावत के पत्र संख्या-C-27/सि.ख.तो./आपदा/2022-23 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि-
- i. शारदा बैराज की अधिकतम क्षमता 06 लाख क्यूसेक है। वर्ष 2013 में शारदा नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण शारदा बैराज से 5.44 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज प्रवाहित हुआ एवं दिनांक 18-19 अक्टूबर, 2021 में शारदा नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण शारदा बैराज से 5.47 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज प्रवाहित हुआ।
- ii. शारदा नदी के दाये पार्श्व पर ग्राम बूम, उचीलीगोठ, गैडाखाली नम्बर-01, 03, 04, सुवागोट, थवालखेड़ा, खेतखेड़ा, फायर स्टेशन, घसियारा मंडी स्थित है। उक्त ग्रामों के समीप शारदा नदी में जगह-जगह आर.बी.एम. जमा होने के कारण नदी में डेल्टा बन गये हैं जिसके कारण से नदी का रूख अपनी मुख्य धारा में न बह कर उक्त ग्रामों की ओर मुड़ गया है। जिससे उक्त ग्रामों की कृषि योग्य भूमि का कटाव व जल भराव के साथ-साथ जान माल की क्षति होने की संभावना बनी हुयी है। उक्त ग्रामों की आबादी व जान-माल की क्षति को बचाने हेतु नदी का चैनलाईजेशन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
- iii. ग्राम गैडाखाली के डाउन स्ट्रीम में स्थित ग्राम सुवागोट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला खनिज न्यास मद के अन्तर्गत 09 मीटर लम्बाई, 06 मी चौड़ाई, 04 मीटर जैँचाई में 04 स्परों का निर्माण का कार्य किया गया है। शारदा नदी के रूख को अपनी मुख्य धारा में नहीं मिलाये जाने पर अत्यधिक जल स्तर बढ़ने से ग्राम सुवागोट में निर्मित 04 स्पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जिससे जानमाल की हानि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- iv. ग्राम उचीलीगोठ के डाउन स्ट्रीम में गैडाखाली के समीप शारदा नदी की चौड़ाई लगभग 1200 मीटर है। मानसून अवधि 2022 से पूर्व नदी के दोनों पार्श्वों से 25 प्रतिशत चौड़ाई को छोड़ते हुए नदी की मुख्य धारा में जमा हुए आर.बी.एम का चैनलाईजेशन किया जायेगा जिसकी लम्बाई 800 मीटर, चौड़ाई लगभग 150 मीटर व गहराई 03 से 04 मीटर है। उक्त ग्रामों की सुरक्षा को देखते हुये शारदा नदी के दाये पार्श्व पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किये जाने अत्यंत आवश्यक है। जिससे कि आगामी मानसून अवधि-2022 से पूर्व उक्त ग्रामों के संभावित खतरे को न्यून किया जा सके।
- v. वन विभाग द्वारा उक्त बैठक में अवगत कराया गया कि मानसून अवधि 2022 से पूर्व आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत उक्त कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने हेतु वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु उक्त क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य संपादित करवाये जाने के दौरान यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त क्षेत्र में किसी भी दशा में नदी क्षेत्र से उपखनिजों की निकासी न की जाये।

दिनांक 13.04.2022 को चम्पावत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी जिसमें सिंचाई विभाग, लोहाघाट चम्पावत द्वारा तर्क दिया गया कि-

1. सर्वप्रथम ऐसे स्थल पर चैनलाईजेशन का कार्य किया जाये जहाँ पर चैनलाईजेशन करने से अधिक प्रभावी समाधान निकल सके। उसके प्रभाव को देखने के उपरान्त ही अन्य स्थानों पर चैनलाईजेशन कार्य किया जाना उचित होगा। ऐसा स्थल गैडाखाली न. 1 के समीप चिह्नित किया गया जिनके तर्क पर विचारोंपरान्त तय किया गया कि सर्वप्रथम गैडाखाली न. 1 पर चैनलाईजेशन कार्य मानसून अवधि 2022 से पूर्व कर लिया जाए एवं आगामी वर्ष ऋतु में इसके प्रभाव को आंकलित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाए।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त बूम से शारदा घाट तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कर लिये जाए।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उपरोक्त यर्णित कार्यों को प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में सिंचाई विभाग लोहाघाट द्वारा सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार, विनीत तोमर, जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चम्पावत आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय-4 की धारा 30 के अन्तर्गत की उपधारा 2(iii), (iv), (v), (xi), (xviii), (xx), धारा 34

(Handwritten signature)

(क), (ख), (घ), (ज), (ट), (ड), अध्याय 11 की धारा 65 की उपधारा 1(क) के अन्तर्गत आदेश पारित करता हूँ कि आगामी मानसून 2022 अवधि के दौरान आम-जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड लोहाघाट, चम्पावत ग्राम उचौलीगोठ के डाउन स्ट्रीम में गैडाखाली न. 1 के समीप शारदा नदी का चैनेलाईजेशन का कार्य तहसील अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों यथा- सिंचाई विभाग, वन विभाग, वन विकास निगम, आदि का अधिकतम उपयोग करते हुये उक्त स्थान पर सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत आपदा न्यूनीकरण एवं बाढ़ सुरक्षात्मक संबंधित कार्य करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

दिनांक: अप्रैल, 2022

(विनीत तोमर)

जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
चम्पावत।

कार्यालय-जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, चम्पावत।

पत्रांक- 15 / xiii-आ.प्र.प्राधि. / DM Act-2005 / शारदा नदी / 2022-23

दिनांक- 19 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

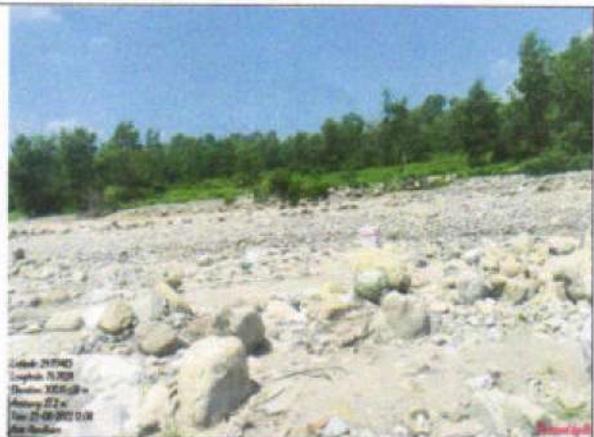
1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, औद्योगिक विकास(खनन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
7. पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
9. अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.डी.एम.ए., चम्पावत।
10. मुख्य अभियन्ता, कुमाँऊ, सिंचाई, हल्द्वानी, नैनीताल।
11. उपजिलाधिकारी, श्री पूर्णागिरी (टनकपुर)।
12. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट।
13. प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर।

(विनीत तोमर)
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
चम्पावत।

Photo Gallery in the matter of O.A. No. 429 of 2022
Nandhaur River



Pic. (01) Downstream of Nandhaur Wildlife Sanctuary



Pic.(02) Border line of Nandhaur Wildlife Sanctuary



Pic.(03) Downstream of Nandhaur Wildlife Sanctuary



Pic.(04) Upstream of River Nandhaur at Machlivan



Pic.(05) Channelization of River Nandhaur



Pic.(06) Channelization of River Nandhaur

Photo Gallery in the matter of O.A. No. 429 of 2022
River Sharda Barrage



Pic.(07) Sharda Barrage Tanakpur



Pic.(08) Upstream of Sharda Barrage



Pic.(09) Proposed Area for Mining in U/S Sharda Barrage



Pic.(10) Channelization of River in U/S Sharda Barrage

[Handwritten signature]